Weekly One Liners 23rd to 29th of March 2026

रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 विजेताओं की सूची

इन पुरस्कारों में विविध श्रेणियों को शामिल किया गया, जो विभिन्न प्रारूपों और भाषाओं में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं।

श्रेणी	विजेता	संस्था/प्रकाशन
प्रिंट (हिंदी)	अवधेश अकोडिया	दैनिक भास्कर
ब्रॉडकास्ट/डिजिटल (हिंदी)	सर्वप्रिय सांगवान	बीबीसी न्यूज़ हिंदी
प्रिंट/डिजिटल (क्षेत्रीय भाषाएं)	मुहम्मद साबिथ एवं अखिल सिवानंद	मातृभूमि
ब्रॉडकास्ट/डिजिटल (क्षेत्रीय भाषाएं)	फौसिया मुस्तफा न्यूज़	मलयालम 24×7
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रिपोर्टिंग	जयश्री नंदी एवं तन्नु जैन	हिंदुस्तान टाइम्स
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (ब्रॉडकास्ट/डिजिटल)	रोहिणी कृष्णमूर्ति एवं ध्रुवल पारेख	डाउन टू अर्थ
'अनकवरिंग इंडिया इनविज़िबल'	विजय पाल डूडी	दैनिक भास्कर
'अनकवरिंग इंडिया इनविज़िबल' (ब्रॉडकास्ट/डिजिटल)	बसंत कुमार	न्यूज़लॉन्ड्री
बिजनेस एवं आर्थिक पत्रकारिता	प्रवीण परमासिवम, मुन्सिफ वेंगटिल एवं आदित्य कालरा	थॉमसन रॉयटर्स
राजनीति एवं सरकार पर रिपोर्टिंग	दीप्तिमान तिवारी	द इंडियन एक्सप्रेस
राजनीति एवं सरकार (ब्रॉडकास्ट/डिजिटल)	ऋषिका कश्यप	डेक्कन हेराल्ड
खेल पत्रकारिता	श्रीकांत धासारथी	डीटी नेक्स्ट
खोजी पत्रकारिता (प्रिंट/डिजिटल)	मृदुलिका झा	आज तक
खोजी पत्रकारिता (ब्रॉडकास्ट)	श्रेया चटर्जी	इंडिया टुडे
फीचर लेखन	विधीशा कुंटामल्ला	द इंडियन एक्सप्रेस
सिविक पत्रकारिता	संदीप दिघे	द टाइम्स ऑफ इंडिया
सिविक पत्रकारिता	श्रेया चटर्जी एवं अरविंद ओझा	इंडिया टुडे
फोटो पत्रकारिता	प्रवीण जैन	द प्रिंट
पुस्तक (गैर-फिक्शन)	अपराजित रामनाथ	पेंगुइन रैंडम हाउस

सुप्रीम कोर्ट ने SC दर्जे पर फैसला सुनाया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के व्यक्तियों तक ही सीमित है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म को अपनाता है, तो उसे तुरंत SC का दर्जा खोना पड़ेगा, भले ही उसका जन्म किसी अनुसूचित जाति में हुआ हो। यह फैसला मार्च 2026 में सुनाया गया और इसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय को बरकरार रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है?

अदालत की पीठ (न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन) ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 पर आधारित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम पूर्णतः लागू होता है और केवल जन्म के आधार पर SC दर्जा बनाए नहीं रखा जा सकता।

संवैधानिक आधार: 1950 का आदेश

अदालत ने अपने निर्णय में 1950 के राष्ट्रपति आदेश की धारा 3 पर जोर दिया। इसके अनुसार:

- शुरुआत में केवल हिंदू धर्म के लोग ही SC के पात्र थे
- 1956 में सिख धर्म और 1990 में बौद्ध धर्म को शामिल किया गया
- लेकिन ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया

कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक प्रावधान बाध्यकारी है और इसमें न्यायिक व्याख्या से बदलाव नहीं किया जा सकता।

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पर प्रभाव

इस फैसले का असर SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर भी पड़ता है। अदालत के अनुसार, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, वह इस अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून केवल SC/ST वर्ग के लिए ही लागू होता है।

SC वर्गीकरण में धर्म का महत्व

अनुसूचित जाति की अवधारणा का संबंध ऐतिहासिक रूप से हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता से रहा है।

- जाति आधारित भेदभाव मुख्य रूप से हिंदू सामाजिक ढांचे से जुड़ा माना गया
- सिख और बौद्ध धर्म को सामाजिक व ऐतिहासिक कारणों से इसमें शामिल किया गया

भारत में अनुसूचित जाति का महत्व

भारत में अनुसूचित जातियां वे समूह हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन्हें कई संवैधानिक लाभ दिए जाते हैं, जैसे:

- शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व
- विशेष कानूनी सुरक्षा

इन जातियों की सूची अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाती है और इसमें कोई भी बदलाव केवल संसद की मंजूरी से ही संभव है।

सुप्रीम कोर्ट पैनल ने केंद्र सरकार से ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 वापस लेने का आग्रह किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक पैनल ने केंद्र सरकार से **ट्रांसजेंडर पर्सन्स (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026** को वापस लेने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं। यह सिफारिश उसी दिन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को भेजी गई, जिस दिन लोकसभा में विधेयक पारित हुआ, जिससे इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन ने की।

पैनल क्यों बनाया गया?

यह समिति अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई थी। यह निर्णय एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें एक ट्रांसजेंडर महिला को उत्तर प्रदेश और गुजरात में उसकी लैंगिक पहचान के कारण शिक्षण नौकरी से हटा दिया गया था।

कोर्ट ने 2019 के ट्रांसजेंडर पर्सन्स (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन में कमियों को देखते हुए यह पैनल बनाया, जिसका उद्देश्य था:

- कानूनी और नीतिगत खामियों की पहचान करना
- समान अवसर का ढांचा सुझाना
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित करना

2026 संशोधन विधेयक के प्रमुख बदलाव

इस विधेयक में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें सबसे विवादास्पद है **स्व-पहचान (Self-Identification) के अधिकार को हटाना**।

यह अधिकार पहले NALSA बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक फैसले में दिया गया था, जिसमें बिना मेडिकल जांच के अपनी लैंगिक पहचान चुनने की अनुमति दी गई थी।

नए विधेयक के तहत:

- लैंगिक पहचान के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा
- जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड (CMO के नेतृत्व में) पहचान तय करेगा
- ट्रांसजेंडर की परिभाषा को सीमित किया गया है

विरोध और जन प्रतिक्रिया

संसद में इस विधेयक का जोरदार विरोध हुआ। कई सांसदों ने इसे विस्तृत जांच के लिए संसदीय समिति को भेजने की मांग की, लेकिन यह मांग अस्वीकार कर दी गई।

संसद के बाहर भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। LGBTQIA+ समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विधेयक:

- लैंगिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है
- अवैज्ञानिक और हस्तक्षेपकारी प्रक्रियाएं थोपता है
- विविध लैंगिक पहचानों को समाप्त करने का खतरा पैदा करता है

सरकार बनाम आलोचक

सरकार का कहना है कि यह विधेयक एक अधिक व्यवस्थित और समावेशी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से लाया गया है।

हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि ये संशोधन पहले से मिले अधिकारों को कमजोर करते हैं और न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। साथ ही, वे इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं।

National Affairs

PRARAMBH 2026 IT जागरूकता अभियान शुरू: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में PRARAMBH 2026 (मिशन विकसित भारत के लिए नीति सुधार और ज़िम्मेदार कार्रवाई) की शुरुआत की। यह आयकर विभाग का एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले 'आयकर अधिनियम, 2025' को प्रभावी ढंग से लागू करना है। यह अभियान प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर चलाया जाने वाला एक बहु-माध्यम (multi-channel) प्रयास है, जो M.A.N.A.V. फ्रेमवर्क (नैतिक और सैद्धांतिक प्रणालियाँ, जवाबदेह शासन, राष्ट्रीय संप्रभुता, सुलभ और समावेशी AI, तथा वैध और न्यायसंगत प्रणालियाँ) द्वारा निर्देशित है। इसकी मुख्य विशेषताओं में करदाताओं को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपग्रेड की गई 'आयकर वेबसाइट 2.0' और AI-सक्षम चैटबॉट 'कर साथी' की शुरुआत शामिल है।

नेशनल डेंटल कमीशन का गठन, डेंटल काउंसिल ऑफ़ इंडिया की जगह लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने मार्च 2026 में नेशनल डेंटल कमीशन (NDC) का गठन किया। इसने नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट, 2023 के तहत डेंटल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DCI) की जगह ली। यह एक्ट 19 मार्च, 2026 को लागू हुआ था। इस नई बनी संस्था का मकसद डेंटल शिक्षा में बदलाव लाना और इसे दुनिया भर के मानकों के हिसाब से बनाना है। इसमें डॉ. संजय तिवारी को चेयरमैन और डॉ. मौसमी गोस्वामी को पार्ट-टाइम सदस्य बनाया गया है। NDC के तहत तीन अपने-आप काम करने वाली संस्थाएँ बनाई गई हैं: अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, डेंटल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड, और एथिक्स और डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड।

NBA ने इनवेसिव एलियन स्पीशीज़ पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक कानूनी संस्था, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) ने मार्च 2026 में इनवेसिव एलियन स्पीशीज़ पर एक कई विषयों के जानकारों वाली एक्सपर्ट कमेटी बनाई। यह कमेटी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट, 2002 (जिसमें 2023 में बदलाव किया गया था) के तहत बनाई गई है। इसका मकसद भारत में बायोडायवर्सिटी और खाने की सुरक्षा को बढ़ते हुए इकोलॉजिकल और सामाजिक-आर्थिक खतरों से बचाना है। उत्तराखंड के पूर्व प्रिंसिपल चीफ़ कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट, धनंजय मोहन को दो साल के लिए चेयरमैन और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ़ फ़िशरीज़ एंड ओशन स्टडीज़ के वाइस चांसलर, ए. बिजु कुमार को को-चेयरमैन बनाया गया है। यह कमेटी इनवेसिव एलियन स्पीशीज़ की एक पूरी नेशनल लिस्ट तैयार करेगी, ज़्यादा खतरे वाली स्पीशीज़ को प्राथमिकता देगी, और उन्हें रोकने, कंट्रोल करने और पूरी तरह खत्म करने के लिए विज्ञान पर आधारित तरीके सुझाएगी।

पश्चिम एशिया संकट के असर से निपटने के लिए सात अधिकार प्राप्त समूहों की घोषणा PM नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च, 2026 को सात अधिकार प्राप्त समूहों के गठन की घोषणा की। इन समूहों का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्गों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने वाले दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों से निपटना है। इन समूहों का नेतृत्व वरिष्ठ सचिव कर रहे हैं, जिनमें विक्रम मिस्री (रक्षा और विदेश मामले), अनुराधा ठाकुर (वित्त और आपूर्ति श्रृंखला), नीरज मित्तल (तेल, LNG और ऊर्जा), रजत कुमार मिश्रा (उर्वरक), निधि खरे (उपभोक्ता मामले और मूल्य स्थिरता), विजय कुमार (परिवहन प्रणालियाँ) और संजय जाजू (संचार) शामिल हैं। इस पहल का लक्ष्य वास्तविक समय की निगरानी और मंत्रालयों के बीच समन्वय के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय तैयारियों को मज़बूत करना है।

गुजरात बना समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य गुजरात विधानसभा ने मार्च 2026 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसके साथ ही, गुजरात उत्तराखंड के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यह विधेयक धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने के लिए एक साझा कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसमें लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण और द्विविवाह पर प्रतिबंध शामिल है। यह कानून गुजरात के सभी निवासियों पर लागू होगा, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों (STs) को छूट दी गई है, जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत संरक्षित हैं।

PM मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख। मार्च 2026 में, PM नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बन गए। उन्होंने अपने पद पर 8,931 दिन पूरे किए और कार्यकारी नेतृत्व में अपना 25वां वर्ष शुरू किया, इस तरह उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उनके कार्यकाल में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्षों से अधिक का समय (2001-2014) और मई 2014 से PM के रूप में बिताया गया समय शामिल है। इसके साथ ही, वह पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी PM बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीन लोकसभा चुनावों (2014, 2019, 2024) में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। डिजिटल दुनिया में उनकी मौजूदगी सबसे मज़बूत वैश्विक डिजिटल उपस्थितियों में से एक है; उनके YouTube पर 30 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर, Instagram पर 100 मिलियन से अधिक फ़ॉलोअर्स और X (पहले Twitter) पर लगभग 106.4 मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं।

कैबिनेट ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए संशोधित UDAN योजना को मंज़ूरी दी। मार्च 2026 में, केंद्रीय कैबिनेट ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) – संशोधित 'उड़े देश का आम नागरिक' (UDAN) को मंज़ूरी दी। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहाँ हवाई सेवाओं की कमी है, और इसके लिए 10 वर्षों (वित्त वर्ष 27-वित्त वर्ष 36) की अवधि में कुल ₹28,840 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस संशोधित कार्यक्रम से लगभग 120 नए गंतव्यों को जोड़ने और लगभग 40 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट ने IVFRT योजना को 2031 तक ₹1,800 करोड़ के बजट के साथ बढ़ाया। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2026 में इमिग्रेशन, वीज़ा, विदेशियों के पंजीकरण और ट्रैकिंग (IVFRT) योजना के विस्तार को मंज़ूरी दी। यह विस्तार 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक (पाँच साल का विस्तार) के लिए है, जिसके लिए कुल ₹1,800 करोड़ का बजट रखा गया है। यह राशि मई 2010 में मंज़ूर किए गए मूल ₹1,011 करोड़ के बजट से ज़्यादा है। यह योजना इमिग्रेशन और विदेशियों अधिनियम, 2025 के अनुरूप है और तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: उभरते तकनीकी नवाचार, मुख्य बुनियादी ढांचे में बदलाव, और प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल। इस योजना को गृह मंत्रालय द्वारा इमिग्रेशन ब्यूरो (BoI) के माध्यम से लागू किया जाता है।

कैबिनेट ने भारत के NDC लक्ष्यों 2031-35 को मंज़ूरी दी; उत्सर्जन की तीव्रता में कमी का लक्ष्य बढ़ाकर 47% किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2026 में 2031-2035 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को मंज़ूरी दी। इसके तहत, 2005 के स्तरों की तुलना में 2035 तक उत्सर्जन की तीव्रता में कमी का लक्ष्य बढ़ाकर 47% कर दिया गया है (यह लक्ष्य 2005-2020 के दौरान हासिल की गई 36% की कमी पर आधारित है)। भारत ने 2035 तक गैर-जीवाश्म ईंधनों से 60% स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने (फरवरी 2026 तक मौजूदा 52.57% से बढ़ाकर) और वनों तथा वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2035 तक 3.5-4 अरब टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है।

रेल मंत्रालय ने 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पहल के तहत पाँच नए सुधार पेश किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 मार्च, 2026 को 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' (52 हफ़्तों में 52 सुधार) पहल के तहत पाँच नए सुधारों की घोषणा की। इसके साथ ही, 2026 में मंज़ूर किए गए कुल सुधारों की संख्या नौ हो गई है, जिनका मुख्य ज़ोर माल ढुलाई की दक्षता, निर्माण की गुणवत्ता और यात्रियों की सुविधा पर है। इन सुधारों में नमक की ढुलाई के लिए स्टेनलेस स्टील कंटेनर (SSC), ऑटोमोबाइल के लिए विशेष वैगन डिज़ाइन (SWD), निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों की पात्रता के कड़े मानदंड (CEC), टिकट रद्द करने के संशोधित नियम (जिनमें 72/24/8 घंटे के स्लॉट शामिल हैं), और ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक डिजिटल बोर्डिंग में बदलाव की अनुमति शामिल है।

लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव पर JPC का कार्यकाल मॉनसून सत्र 2026 तक बढ़ाया। लोकसभा ने मार्च 2026 में, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का कार्यकाल, मॉनसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया। इससे समिति को संवैधानिक, कानूनी और लॉजिस्टिकल चुनौतियों की जाँच करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। यह समिति संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है। इन विधेयकों में पूरे देश में चुनाव चक्रों को एक साथ लाने का प्रस्ताव है, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जा सकें।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' शुरू किया गया। भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' शुरू किया। इसका मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर भारत आने वाले 22 ऊर्जा जहाजों को सुरक्षा देना और उन्हें एस्कॉर्ट करना था। इसके लिए 5 से ज़्यादा फ्रंटलाइन युद्धपोत तैनात किए गए। यह मिशन LNG, LPG और कच्चे तेल की ज़रूरी खेपों को सुरक्षा देता है। इस मिशन के तहत पाइन गैस, जग वसंत, शिवालिक और नंदा देवी जैसे जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट करने का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

प्रोजेक्ट 'वायु बाण' - भारत का पहला हेलीकॉप्टर से गिराया जाने वाला ड्रोन शुरू किया गया। भारतीय वायु सेना ने मार्च 2026 में 'वायु बाण' लॉन्च किया। यह भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाले अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS) का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही भारत, USA और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास यह क्षमता है। यह छोटा और अपने आप काम करने वाला ड्रोन हेलीकॉप्टर को 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से ही टारगेट पर हमला करने की सुविधा देता है। इससे एयरक्रू MANPADS की रेंज से बाहर सुरक्षित रहता है।

सड़क-रेल पुल प्रोजेक्ट के लिए 'PRISM-SG पोर्टल' लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (MoRTH) और अश्विनी वैष्णव (रेलवे) ने 26 मार्च 2026 को नई दिल्ली में मिलकर 'PRISM-SG पोर्टल' लॉन्च किया। इस पोर्टल से 'रोड ओवर ब्रिज' (ROBs) के लिए मंज़ूरी मिलने में लगने वाला समय 12 महीने से घटकर 3-4 महीने रह जाएगा। यह 'एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ़्लो' है जो QAP, WPSS, FSI और RTMS को एक साथ जोड़ता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट बिना किसी रुकावट के हो पाता है।

संस्कृति मंत्रालय ने लोक-आदिवासी संगीत को बढ़ावा देने के लिए YouTube के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति मंत्रालय ने मार्च 2026 में YouTube के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भारत के लोक और आदिवासी संगीत को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। यह पहल, जिसका नेतृत्व संयुक्त कार्य बल (JTF) कर रहा है और जिसमें YouTube नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल' विज़न के अनुरूप काम करने का लक्ष्य रखती है।

डाक विभाग ने आदिवासी ई-कॉमर्स के लिए TRIFED के साथ साझेदारी की। डाक विभाग ने मार्च 2026 में TRIFED (जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन) के साथ 2 साल की लॉजिस्टिक्स साझेदारी के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए, ताकि 'ट्राइब्स इंडिया' मार्केटप्लेस के माध्यम से आदिवासी उत्पादों की डिलीवरी की जा सके। डाक विभाग (DoP) स्पीड पोस्ट डिलीवरी के लिए अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का लाभ उठाएगा, जिसके लिए 'पोस्ट नेशन अकाउंट सुविधा' के तहत एक समर्पित BNPL खाता बनाया गया है।

भारतीय सेना और IITM प्रवर्तक के बीच रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए MoU। भारतीय सेना के EME कोर ने मार्च 2026 में चेन्नई स्थित IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज़ फाउंडेशन के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को गति देना है। चेन्नई के अवाडी में एक 'नोडल इंडिजिनाइज़ेशन सेंटर' (NIC) स्थापित किया गया है, जो 'तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर' (TNDC) का लाभ उठाते हुए रक्षा नवाचार के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च, 2026 को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च, 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे ₹11,200 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसकी सालाना यात्री क्षमता 12 मिलियन है। इस एयरपोर्ट में 3,900 मीटर का रनवे है, जिसे 'नेट-ज़ीरो एमिशन' सुविधा के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल भी है जो सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन कार्गो संभाल सकता है, और 40 एकड़ में फैली MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल) सुविधा भी मौजूद है।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया गया। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में 'जन विश्वास विधेयक 2026' पेश किया। इस विधेयक में 23 मंत्रालयों के तहत आने वाले 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। यह विधेयक 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और 67 प्रावधानों में संशोधन करता है, ताकि लोगों का जीवन आसान हो सके। इसके तहत, छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए जेल की सज़ा की जगह आर्थिक जुर्माना या चेतावनी का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने 2024-25 के लिए उर्वरक सब्सिडी हेतु ₹1.77 लाख करोड़ आवंटित किए। उर्वरक विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उर्वरक सब्सिडी हेतु ₹1,77,129.50 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके ज़रिए 'पोषक तत्व आधारित सब्सिडी' (NBS) योजना के माध्यम से उर्वरकों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सब्सिडी पर होने वाले खर्च में गिरावट का रुख देखा गया है—यह वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1,95,420.51 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 में ₹2,54,798.93 करोड़ था। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि सरकार ने सब्सिडी का रणनीतिक रूप से युक्तिसंगत (rationalize) किया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों तक उर्वरकों की पहुँच बनी रहे।

पारदर्शिता के लिए TV रेटिंग पॉलिसी (TRP) 2026 अधिसूचित। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 27 मार्च, 2026 को TV रेटिंग पॉलिसी 2026 जारी की, जिसमें TV रेटिंग एजेंसियों के लिए न्यूनतम नेट वर्थ की आवश्यकता को ₹20 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है। यह पॉलिसी 50% स्वतंत्र निदेशकों, 18 महीनों के भीतर 80,000 मीटर वाले घरों तक विस्तार (और अंततः 1,20,000 घरों तक), तथा बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तिमाही आंतरिक और वार्षिक बाहरी ऑडिट को अनिवार्य बनाती है।

States in the News

तेलंगाना बजट 2026-27: ₹3.24 लाख करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याण पर ज़ोर। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मार्च 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तेलंगाना का बजट पेश किया। इसका कुल आकार ₹3,24,234 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 26 (₹3.04 लाख करोड़) की तुलना में लगभग ₹20,000 करोड़ ज़्यादा है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुमान ₹17,82,198 करोड़ लगाया गया है, जिसमें 10.7% की वृद्धि दर (राष्ट्रीय औसत से 2.7% ज़्यादा) है। सरकार का लक्ष्य 2034 तक ₹1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। मुख्य आवंटनों में राजस्व व्यय के लिए ₹2,34,406 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए ₹47,267 करोड़ शामिल हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, कल्याणकारी कार्यक्रमों, शहरी विस्तार और आर्थिक विकास पर ज़ोर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27: ₹54,928 करोड़, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ज़ोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्च 2026 में वित्त वर्ष 27 के लिए हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया। इसका आकार ₹54,928 करोड़ था (पिछले वर्ष के ₹58,514 करोड़ से ₹3,586 करोड़ कम)। इस बजट में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, सामाजिक कल्याण, हरित ऊर्जा, ग्रामीण विकास और रोज़गार सृजन पर ज़ोर दिया गया है। बजट में ₹6,577 करोड़ के राजस्व घाटे (RD) का अनुमान लगाया गया है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां (RR) ₹40,361 करोड़ हैं, जबकि राजस्व व्यय (RE) ₹46,938 करोड़ है। साथ ही, राजकोषीय घाटा ₹9,698 करोड़ (GSDP का 3.49%) रहने का अनुमान है। राज्य की अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें GSDP का अनुमान ₹2,54,000 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय (PCI) का अनुमान ₹2,83,626 है।

दिल्ली बजट 2026-27: ₹1.03 लाख करोड़, ग्रीन डेवलपमेंट पर ज़ोर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मार्च 2026 में FY27 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया, जिसका कुल खर्च ₹1,03,700 करोड़ था। यह पिछले साल (₹1 लाख करोड़) के मुकाबले 3.7% ज़्यादा है। इसे "ग्रीन बजट" बताया गया है, जिसमें पर्यावरण की स्थिरता पर खास ज़ोर दिया गया है। कुल बजट का लगभग 21% हिस्सा ग्रीन पहलों के लिए रखा गया है, ताकि हवा में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। मुख्य आवंटनों में शिक्षा के लिए ₹19,148 करोड़, स्वास्थ्य के लिए ₹12,645 करोड़, नगर निगम के लिए ₹11,666 करोड़ और दिल्ली जल बोर्ड के लिए ₹9,000 करोड़ शामिल हैं। बजट में FY27 के लिए ₹9,092 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान लगाया गया है। साथ ही, GSDP में 5.09% की बढ़ोतरी का अनुमान है और उम्मीद है कि FY26 में GSDP बढ़कर ₹13.27 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगी (जो FY25 में ₹12.13 लाख करोड़ थी)।

UP CM ने 'Nivesh Mitra 3.0' लॉन्च किया, जिससे व्यापार करना और भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 मार्च 2026 को लखनऊ में 'Nivesh Mitra 3.0' लॉन्च किया। यह एक अपग्रेडेड डिजिटल सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है, जो 43 विभागों की 530 से ज़्यादा सेवाओं को PAN-आधारित सिंगल यूज़र ID का इस्तेमाल करके 200 से भी कम आसान डिजिटल सेवाओं में जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म में एक AI-आधारित चैटबॉट भी है, जो रियल-टाइम SMS अलर्ट और एप्लीकेशन ट्रैकिंग के साथ तुरंत मदद देता है। इसके साथ ही, 'UP Private Business Park Development Scheme-2025' और 'Plug-and-Play Industrial Sheds Scheme' भी शुरू की गईं, ताकि सरकारी ज़मीन और निजी निवेश के ज़रिए औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026: इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च हुआ। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट (BES 2026) का पहला संस्करण 19-22 मार्च, 2026 को यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने "Electrifying Growth. Empowering Sustainability. Connecting Globally" (विकास को बिजली देना। स्थिरता को सशक्त बनाना। विश्व स्तर पर जुड़ना) की थीम के साथ किया। इस कार्यक्रम के दौरान, इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल (www.indiancarbonmarket.gov.in) लॉन्च किया गया। यह पोर्टल कार्बन मार्केट को लागू करने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीय मंच है। इस समिट में मलावी, ताजिकिस्तान, मॉरीशस, किर्गिस्तान और रूस जैसे देशों के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें भी हुईं। इसका अगला संस्करण (BES 2028) गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा।

तेलंगाना ने बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की: पारिवारिक जीवन बीमा और कैशलेस स्वास्थ्य योजना। तेलंगाना राज्य बजट 2026 में 'इंदिरम्मा पारिवारिक जीवन बीमा योजना' (जो 2 जून, 2026 को शुरू होगी) की घोषणा की गई। इस योजना के तहत लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार ₹5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा, जिससे परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। 'कैशलेस स्वास्थ्य योजना', जिसे राजीव आरोग्यश्री ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया गया है, 23.51 लाख लाभार्थियों को कवर करती है। इनमें सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित शामिल हैं, जिन्हें 1,998 बीमारियों के लिए इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ₹1.20 करोड़ का दुर्घटना बीमा और ₹10 लाख का टर्म जीवन बीमा (60 वर्ष की आयु तक) भी इस योजना में शामिल है।

GSI ने कालिंजर किला पहाड़ी को राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित किया। उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में स्थित कालिंजर किला पहाड़ी को मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा एक राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित किया गया। यह घोषणा इसकी दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचनाओं, ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए की गई। इस स्थल पर 'एपार्कियन अनकन्फ़ॉर्मिटी' (Eparchaean Unconformity) मौजूद है, जो लगभग 2.5 अरब साल पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर 1.2 अरब साल पुराने कैमूर बलुआ पत्थर की परत को दर्शाती है। यह पृथ्वी के दीर्घकालिक विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण, अलग-अलग भूवैज्ञानिक युगों को प्रदर्शित करता है। इस दर्जे से बांदा ज़िले में पर्यटन और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलने और कालिंजर किले को खजुराहो स्मारक समूह तथा चित्रकूट के साथ एक क्षेत्रीय पर्यटन सर्किट के रूप में प्रचारित करने की उम्मीद है।

गुजरात ने 'सुगम डिजिटल गुजरात पहल' के तहत 20 नागरिक सेवाओं को डिजिटल किया। गुजरात सरकार ने 23 मार्च 2026 को घोषित 'सुगम डिजिटल गुजरात पहल' के तहत, नागरिकों द्वारा सबसे ज़्यादा मांग वाली 20 सेवाओं को डिजिटल कर दिया है। इसके माध्यम से 'डिजिटल गुजरात पोर्टल' के ज़रिए बिना आमने-सामने आए (faceless), बिना नकद लेन-देन (cashless) और बिना कागज़ के (paperless) शासन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाँच अलग-अलग विभागों में डिजिटल की गई सेवाओं में जाति प्रमाण पत्र (SC, SEBC), आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सेवाएँ, प्रमाणित दस्तावेज़, ST प्रमाण पत्र और तैयार शपथ पत्र शामिल हैं। इन सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण, DigiLocker, eSign और UPI भुगतान जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। इस पहल से सेवाओं की मंज़ूरी में लगने वाले समय में कमी आने और सरकारी दफ़्तरों में व्यक्तिगत रूप से जाने की निर्भरता कम होने की उम्मीद है, जिससे सेवाओं की डिलीवरी तेज़ और अधिक कुशल हो सकेगी।

सिक्किम की स्तुति प्रधान वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 के लिए चुनी गईं। सिक्किम की स्तुति प्रधान को मार्च 2026 में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट (WYP) में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जो वैश्विक नीति और कूटनीति में भारत की बढ़ती युवा भूमिका को दर्शाता है। उन्हें संसदीय बहस में उनकी उत्कृष्टता के लिए पहचान मिली और उन्होंने 'विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025' में राज्य विजेता का खिताब हासिल किया; साथ ही, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर सिक्किम के लोक भवन में उन्हें विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित भी किया गया।

साध्वी निरंजन ज्योति ने NCBC अध्यक्ष का पदभार संभाला। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अमरावती नगर निगम की पूर्व महापौर श्रीमती किरण उमेश महाले ने NCBC सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला; ये दोनों ही अपने साथ सामाजिक कल्याण और शासन-प्रशासन का व्यापक अनुभव लेकर आई हैं, जिससे आयोग के जनादेश को और अधिक मजबूती मिलेगी।

International Affairs

भारत और इंडोनेशिया ने योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सहयोग किया। भारत और इंडोनेशिया ने 16 मार्च, 2026 को जकार्ता में एक संयुक्त पहल की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करना है, जिससे सांस्कृतिक कूटनीति और विरासत संरक्षण को मजबूती मिलेगी। यह मंदिर, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति (शिव, विष्णु और ब्रह्मा) को समर्पित है और इसे 1991 में UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। इस जीर्णोद्धार कार्य में 'एनास्टाइलोसिस' पद्धति का उपयोग किया जाएगा, जो एक वैज्ञानिक पुरातात्विक संरक्षण तकनीक है। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव प्रदान करेगा।

नई दिल्ली में भारत-इटली के बीच 9वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन। भारत और इटली ने 20 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) का 9वां दौर आयोजित किया। इस परामर्श का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और इटली के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय की महानिदेशक निकोलेट्टा बोंबार्डिएरे ने किया। दोनों पक्षों ने 'संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (JSAP) 2025-29' की प्रगति की समीक्षा की। इस कार्य योजना में व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा, सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों पक्ष आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (CFT) की संयुक्त पहल को तेज करने और पहले 'समुद्री सुरक्षा संवाद (MSD)' का आयोजन करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही, दोनों देशों ने 10वें FOC का आयोजन इटली में करने का निर्णय लिया।

भारत और भूटान ने डाक सहयोग को मज़बूत करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए। भारत और भूटान ने 19-22 मार्च, 2026 को थिम्पू में, संचार मंत्रालय की सचिव (डाक) वंदिता कौल की यात्रा के दौरान, डाक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU ने इंडिया पोस्ट और भूटान पोस्ट के बीच डाक संचालन, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं और फिलाटेली (डाक टिकट संग्रह) जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया है। इस MoU के तहत एक प्रमुख पहल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन–यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPU–UPI) क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस सिस्टम की शुरुआत है।

भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में 'अभ्यास काकाडू 2026' में भाग लिया। भारतीय नौसेना के एक फ्रिगेट, INS नीलगिरि ने मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 'अभ्यास काकाडू 2026' के समुद्री चरण में भाग लिया। यह भागीदारी उसकी पश्चिमी प्रशांत तैनाती का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। 'अभ्यास काकाडू 2026' के 17वें संस्करण में 19 से अधिक देशों और 6,000 कर्मियों ने भाग लिया। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के जर्विस बे से लेकर डार्विन तक के क्षेत्र में फैला हुआ था, और 21 मार्च, 2026 को सिडनी हार्बर में एक 'फ्लीट रिव्यू' आयोजित किया गया, जो एक दशक से भी अधिक समय में विदेशी युद्धपोतों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। INS नीलगिरि के चालक दल ने डार्विन में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के दौरान 'काकाडू शील्ड ट्रॉफी' जीती, जिसने भारत की समुद्री शक्ति और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ उसकी आपसी सहयोग क्षमता (interoperability) का प्रदर्शन किया।

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026: पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित; भारत 13वें स्थान पर। मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (IEP) द्वारा जारी 'ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026' ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में 8.574 का स्कोर मिला है। 2025 में पाकिस्तान में 1,139 मौतें और 1,045 आतंकवादी घटनाएँ दर्ज की गईं (जो 2013 के बाद से मौतों का सबसे ऊँचा स्तर है)। भारत 6.428 के स्कोर के साथ 13वें स्थान पर रहा, जिसके बाद अफगानिस्तान (6.678 के साथ 11वें स्थान पर) रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में आतंकवादी घटनाएँ 2020 की तुलना में लगभग छह गुना ज़्यादा थीं, जबकि आतंकवाद से संबंधित मौतों में 28% की कमी आई और यह 2025 में 5,582 रह गईं, जो वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026: IIT-ISM धनबाद और IIM अहमदाबाद वैश्विक स्तर पर 21वें स्थान पर। मार्च 2026 में जारी 'QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026' के 16वें संस्करण में, झारखंड के धनबाद स्थित 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी – इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स' (IIT-ISM) को 'इंजीनियरिंग – मिनरल एंड माइनिंग' श्रेणी में वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान मिला। वहीं, गुजरात के अहमदाबाद स्थित 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट' (IIM) ने 'बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज' और 'मार्केटिंग' – दोनों ही श्रेणियों में 21वां स्थान हासिल किया। भारत में अब 99 संस्थान (2025 के 79 संस्थानों से बढ़कर) हैं, जिनकी 599 विषय प्रविष्टियाँ हैं और 12 संस्थानों को मिलाकर शीर्ष-50 विषय रैंकिंग में कुल 27 स्थान प्राप्त हुए हैं। वैश्विक स्तर पर अमेरिका 228 संस्थानों और 37 विषयों में प्रथम स्थान के साथ सबसे आगे है, जबकि भारत प्रविष्टियों की संख्या के आधार पर चौथी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली बन गया है।

UNESCO ने अघनाशिनी-वेदवती नदी-जोड़ो परियोजना पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने मार्च 2026 में प्रस्तावित अघनाशिनी-वेदवती नदी-जोड़ो परियोजना पर चिंता व्यक्त की, और भारत से आग्रह किया कि वह 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत विश्व धरोहर संरक्षण मानदंडों का सख्ती से पालन करे। इस परियोजना के तहत अघनाशिनी नदी से लगभग 35 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट (tmc ft) पानी वेदवती नदी में मोड़ने की योजना है, जिससे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक बदलाव और हज़ारों परिवारों के प्रभावित होने की चिंताएँ बढ़ गई हैं; ये परिवार अपनी आजीविका, कृषि और जल सुरक्षा के लिए इसी नदी प्रणाली पर निर्भर हैं।

नई दिल्ली में 'एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस' का शुभारंभ। दस से अधिक देशों के वरिष्ठ राजदूतों, राजनयिकों, नीति निर्माताओं और कृषि-व्यवसाय जगत के नेताओं ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से 'एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस' (AAAA) का शुभारंभ किया। यह एक नया संस्थागत मंच है जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार, कृषि सहयोग, निवेश और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को मज़बूत करना है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक 'धारा 8 गैर-लाभकारी संगठन' के रूप में स्थापित, AAAA पाँच मुख्य स्तंभों के माध्यम से कार्य करता है: व्यापार और बाज़ार पहुँच, प्रौद्योगिकी और नवाचार हस्तांतरण, निवेश और वित्त, नीति मानक और कृषि कूटनीति, तथा क्षमता निर्माण और ज्ञान का आदान-प्रदान।

कैरोलिना मारिन ने प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। स्पेनिश ओलंपिक और विश्व बैडमिंटन चैंपियन कैरोलिना मारिया मारिन मार्टिन ने मार्च 2026 में, 32 साल की उम्र में, घुटने की तीसरी गंभीर चोट से उबर न पाने के कारण संन्यास की घोषणा कर दी। वह 66 हफ़्तों तक विश्व की नंबर एक खिलाड़ी रहीं, ओलंपिक स्वर्ण पदक (रियो 2016) जीता—ऐसा करने वाली वह एकल वर्ग में खिताब जीतने वाली पहली गैर-एशियाई महिला बनीं—और 3 विश्व चैंपियनशिप (2014, 2015, 2018) अपने नाम कीं।

IOC ने ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग की सुरक्षा के लिए नई नीति को मंज़ूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने मार्च 2026 में 'ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग की सुरक्षा' नामक एक ऐतिहासिक नीति को मंज़ूरी दी, जो LA28 ओलंपिक (14-30 जुलाई, 2028) से प्रभावी होगी। इस नीति के तहत, महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ियों का SRY-नेगेटिव होना अनिवार्य है; SRY-पॉजिटिव खिलाड़ी—जिनमें XY ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं—प्रतिस्पर्धा के लिए अयोग्य माने जाएँगे। हालाँकि, CAIS के मामलों में छूट दी गई है, और कुछ विशिष्ट DSD मामलों में भी अपवाद लागू होंगे, बशर्ते उन मामलों में टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा कोई अतिरिक्त लाभ न हो।

संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYWF 2026) घोषित किया, जिसमें कृषि क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई। भारत में, 80% ग्रामीण महिलाएँ कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में लगी हुई हैं (33% मज़दूरों के रूप में, 48% किसानों के रूप में); भारत ने नई दिल्ली में 'कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाएँ' (GCWAS-2026) पर वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी की, जिसमें लैंगिक-समावेशी नीतियों और जलवायु-अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बालेंद्र शाह ने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता और पूर्व रैपर बालेंद्र शाह (35) ने 27 मार्च, 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह तब हुआ जब RSP ने 5 मार्च, 2026 को हुए संसदीय चुनावों में 275 में से 182 सीटें हासिल कीं। उन्होंने सुशीला कार्की (अंतरिम प्रधानमंत्री) का स्थान लिया और 138 सीटों के बहुमत के आँकड़े को पार कर लिया, जिससे नेपाल की संघीय व्यवस्था के तहत पहली बहुमत वाली सरकार का गठन संभव हो सका।

NASA ने लूनर गेटवे प्लान रद्द किया, $20 बिलियन के मून सरफेस बेस की घोषणा की। NASA ने मार्च 2026 में अपने आर्टेमिस प्रोग्राम में एक बड़ा बदलाव करते हुए, लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन को रद्द कर दिया और उसकी जगह $20 बिलियन की लागत से चंद्रमा की सतह पर एक बेस बनाने की घोषणा की। NASA ने 2028 से पहले "स्पेस रिएक्टर 1 फ्रीडम" अंतरिक्ष यान के साथ परमाणु-संचालित मंगल मिशन की योजनाओं का भी खुलासा किया; इस मिशन में उन्नत परमाणु-विद्युत प्रणोदन (nuclear electric propulsion) तकनीक का इस्तेमाल होगा और मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे, जबकि चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हुए हैं। अमेरिका स्थित 'मॉर्निंग कंसल्ट' के सर्वेक्षण (2-8 मार्च, 2026) के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% अनुमोदन रेटिंग और 26% अस्वीकृति रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हुए हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के गाय पारमेलिन (62%) और दक्षिण कोरिया के ली जे-म्युंग (62%) को पीछे छोड़ दिया है। अन्य प्रमुख वैश्विक नेताओं की रैंकिंग इस प्रकार है: डोनाल्ड ट्रम्प (39%), कीर स्टारमर (24%), फ्रेडरिक मर्ज़ (20%), और इमैनुएल मैक्रॉन (17%)।

Agreements/MoUs Signed

FSI और BISAG-N ने वानिकी में जियोस्पेशियल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने, देहरादून, उत्तराखंड में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SC-NBWL) की स्थायी समिति की 90वीं बैठक के दौरान, भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU का उद्देश्य वानिकी और पर्यावरण प्रबंधन में जियोस्पेशियल तकनीकों के उपयोग को बढ़ाना है। इस MoU का लक्ष्य बेहतर वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और डेटा-आधारित निर्णय सहायता प्रणालियों के लिए रिमोट सेंसिंग और AI/ML-आधारित उपकरणों के उपयोग को मजबूत करना है।

NPC ने पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए MoEF&CC के साथ समझौता किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अधीन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) ने, मार्च 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत NPC, पर्यावरण ऑडिट नियम (EAR) 2025 के तहत 'पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी' (EADA) के रूप में कार्य करेगा; इन नियमों की आधिकारिक अधिसूचना 29 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी। NPC की भूमिका में ऑडिटरों का प्रमाणन और पंजीकरण, पात्रता मानदंड और जांच पद्धतियों का विकास, प्रदर्शन की निगरानी, दिशानिर्देश जारी करना, और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना शामिल है। इन अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में पर्यावरण ऑडिटरों के पंजीकरण का निलंबन, रद्दीकरण या नवीनीकरण शामिल हो सकता है।

RRU और SSB अकादमी ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्रालय (MHA) के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल (SSB) अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मज़बूत किया जा सके। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, RRU, SSB अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक मान्यता प्रदान करेगा। साथ ही, यह संकाय विशेषज्ञता, शिक्षण उपकरण और विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं सहित संसाधनों के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा, जबकि मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगा और संयुक्त रूप से अतिरिक्त पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करेगा।

DPIIT ने उत्पाद-आधारित स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए Blue Star के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में, एक अग्रणी एयर कंडीशनिंग कंपनी, Blue Star Limited के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, ताकि भारत में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और स्टार्टअप्स को सहायता दी जा सके। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है, जिसमें हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) प्रौद्योगिकियों, डिजिटल समाधानों और उन्नत विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत स्टार्टअप्स को उद्योग विशेषज्ञों से मार्गदर्शन (मेंटरशिप), R&D प्रयोगशालाओं तक पहुँच और बुनियादी ढाँचे के सहयोग के लिए परीक्षण सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए Razorpay के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए; 'Startup Sahayak' प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के तहत, ने 25 मार्च, 2026 को Razorpay के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में, वित्तीय उपकरण, तकनीकी और सलाहकार सहायता, और डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करके सशक्त बनाना है। एक समर्पित प्लेटफ़ॉर्म, 'Startup Sahayak' लॉन्च किया गया है, जो कंपनी के पंजीकरण, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तक पहुँच, और फंडिंग के अवसरों पर मार्गदर्शन सहित शुरू से अंत तक (end-to-end) सहायता प्रदान करता है। इसे Startup India Hub (SIH) और Bharat Startup Grand Challenge (BSGC) के माध्यम से व्यवस्थित किया गया है।

BHASHINI–PFRDA ने बहुभाषी पेंशन सेवाओं को सक्षम करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत Digital India BHASHa Interface for India (BHASHINI) प्रभाग (DIBD) और वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 25 मार्च, 2026 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर 'BHASHINI for Seva–Sanchalan' पहल के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में पेंशन सेवाओं की बहुभाषी पहुँच को बढ़ाना है। यह पहल PFRDA के प्लेटफ़ॉर्म पर सभी 22 आठवीं अनुसूची की भाषाओं में बहुभाषी पहुँच को सक्षम बनाती है। इन भाषाओं में हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू और संस्कृत शामिल हैं। इसके लिए BHASHINI का उपयोग एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे (Digital Public Infrastructure) के रूप में किया जाता है, जिसमें वास्तविक समय (real-time) के अनुवाद और प्रासंगिक प्रसंस्करण के लिए AI मॉडलों का लाभ उठाया जाता है।

कोचीन चैंबर ने द्विपक्षीय व्यापार को मज़बूत करने के लिए लातवियाई चैंबर के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए। कोचीन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (CCCI) ने मार्च 2026 में, लातविया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, लातवियाई चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (LCCI), लातविया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। CCCI (जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी और जो केरल का सबसे पुराना चैंबर ऑफ़ कॉमर्स है) भारत का दूसरा और दक्षिण भारत का पहला ऐसा चैंबर ऑफ़ कॉमर्स बन गया, जिसने LCCI के साथ समझौता किया है; इससे फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा और लकड़ी उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार के महत्वपूर्ण अवसर खुल गए हैं।

बहुभाषी पेंशन सेवाओं के लिए BHASHINI-PFRDA MoU। MeitY के अंतर्गत डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीज़न (DIBD) और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने "BHASHINI for Seva–Sanchalan" पहल के तहत एक MoU पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग AI-संचालित रीयल-टाइम अनुवाद और वॉइस-सक्षम इंटरफेस का उपयोग करके, आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं (हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, संस्कृत) में पेंशन सेवाओं तक पहुँच को संभव बनाता है, जिससे बहुभाषी डिजिटल शासन और समावेशी वित्तीय सेवाओं को मज़बूती मिलती है।

Books and Authors

विलियम डेलरिम्पल ने 'द गोल्डन रोड' के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 जीता। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल को मार्च 2026 में उनकी किताब "द गोल्डन रोड: हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड" के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 से सम्मानित किया गया। यह किताब ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुरस्कार, जिसका प्रबंधन नीमन फाउंडेशन फॉर जर्नलिज़्म और कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ जर्नलिज़्म द्वारा किया जाता है, 10,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि प्रदान करता है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट ऐतिहासिक लेखन को मान्यता देता है, जिसमें बौद्धिक गहराई, साहित्यिक उत्कृष्टता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता पर विशेष ज़ोर दिया जाता है। यह किताब डेलरिम्पल के दशकों के शोध पर आधारित है और प्राचीन भारत को वैश्विक इतिहास के केंद्र में रखकर पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देती है।

कैलाश सत्यार्थी की किताब 'करुणा: द पावर ऑफ़ कम्पैशन' लॉन्च हुई। 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई किताब, जिसका शीर्षक 'करुणा: द पावर ऑफ़ कम्पैशन' है, को मार्च 2026 में 'सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कम्पैशन' (SMGC) ने हार्पर कॉलिन्स इंडिया के सहयोग से औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी भी मौजूद थीं। यह किताब करुणा को एक ऐसे बदलाव लाने वाले और सक्रिय बल के रूप में पेश करती है, जो असमानता और संघर्ष जैसे वैश्विक संकटों से निपटने में मददगार है। साथ ही, यह 'कम्पैशन कोशेंट' (CQ) की अवधारणा से भी परिचय कराती है—जो व्यक्तियों और संगठनों में करुणा को मापने और बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका है।

बंगाली लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया। जाने-माने बंगाली लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को मार्च 2026 में उनके उपन्यास 'हारा पार्वती कथा (2020)' के लिए 35वें सरस्वती सम्मान (2025) के लिए चुना गया; यह बंगाली साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। के. के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया सरस्वती सम्मान, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मानों में से एक है। यह सम्मान संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिया जाता है। इसके तहत 15 लाख रुपये की नकद राशि के साथ-साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भी प्रदान की जाती है।

Banking/Economy/Business News

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने महिला SHG के लिए UPI-लिंक्ड क्रेडिट लाइन लॉन्च की। भारत के अग्रणी पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (BoB) ने मार्च 2026 में, वेरिफ़ाइड महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों के लिए यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) पर क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ़्ट (OD) सुविधा लॉन्च की। ये वे सदस्य हैं जिनके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खाते हैं, जिससे योग्य महिलाओं को OD के रूप में ₹5,000 तक की राशि मिल सकेगी। BoB देश का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने इस तरह का डिजिटल क्रेडिट समाधान लॉन्च किया है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI), इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA), और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के सहयोग से लॉन्च किया गया है।

RBI ने जमा नियमों का पालन न करने पर HSBC पर ₹31.80 लाख का जुर्माना लगाया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च 2026 में, हॉन्गकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया (HSBC India) पर ₹31.80 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशियों से संबंधित नियामक निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया था। बैंक बिना दावे वाली जमा राशियों का एक खोजने योग्य डेटाबेस बनाए रखने में विफल रहा, उसने बिना दावे वाली जमा राशि के संदर्भ संख्या (UDRN) जेनरेट नहीं किए, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A के तहत जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) कोष में हस्तांतरित जमा राशियों में भी कमियाँ पाई गईं।

गोल्डमैन सैक्स ने CY26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 5.9% किया। मार्च 2026 में, गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2026 (CY26) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की ग्रोथ का अनुमान घटाकर 5.9% कर दिया; यह ईरान युद्ध से पहले के उसके 7% के अनुमान से कम है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि CY26 में भारत में महंगाई बढ़कर 4.6% हो जाएगी, जबकि पहले इसका अनुमान 3.9% था; साथ ही, भारत का चालू खाता घाटा (CAD) भी CY26 में बढ़कर GDP का 2% होने की उम्मीद है। बैंक ने दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए अपने ग्रोथ अनुमान को भी CY26 में घटाकर 6.5% कर दिया।

S&P ग्लोबल ने FY27 के लिए भारत की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया, ग्रोथ आउटलुक में सुधार। मार्च 2026 में, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (S&P) ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट्स (bps) बढ़ाकर 7.1% कर दिया। यह कदम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश की आर्थिक गति में एजेंसी के भरोसे को दर्शाता है। रेटिंग एजेंसी ने अपने अन्य अनुमानों में भी सुधार किया है: FY28 के लिए अनुमान बढ़ाकर 7.2% (20 bps की वृद्धि) और FY29 के लिए 7.0% (इसमें भी 20 bps की वृद्धि) किया गया है। S&P ने अनुमान लगाया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई FY26 के 2.5% से बढ़कर FY27 में 4.3% हो जाएगी।

Razorpay ने भारत में वॉइस-बेस्ड, कई भाषाओं वाला डिजिटल कॉमर्स शुरू करने के लिए Sarvam AI के साथ पार्टनरशिप की। Razorpay, जो एक भारतीय फिनटेक कंपनी है, ने मार्च 2026 में Sarvam AI के साथ पार्टनरशिप की। Sarvam AI एक भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप है। इस पार्टनरशिप का मकसद भारत में वॉइस-बेस्ड और कई भाषाओं वाले डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन पेश करना है। इस सहयोग से यूज़र्स अपनी पसंद की भाषा में वॉइस कमांड देकर प्रोडक्ट खोज सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए Sarvam AI के मॉडल्स और एजेंटिक टेक्नोलॉजी स्टैक को Razorpay के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। यह फीचर शुरू में Sarvam AI के Indus App पर लॉन्च किया गया था, जिसमें Swiggy वॉइस-बेस्ड खाना ऑर्डर करने के लिए शुरुआती पार्टनर बना।

L&T Finance, United Nations Global Compact का सिग्नेटरी बना। L&T Finance Ltd. (LTF) मार्च 2026 में United Nations Global Compact (UNGC) का सिग्नेटरी बन गया। यह इसकी सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस (ESG) फ्रेमवर्क को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस कदम से LTF के नैतिक तरीकों की पुष्टि होती है और इसकी लंबी अवधि की रणनीति, UNGC के मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार-विरोधी सिद्धांतों के साथ मेल खाती है। LTF, 'Global Compact के दस सिद्धांतों' को लागू करने में हुई अपनी प्रगति पर हर साल रिपोर्ट देगा। इसके अलावा, यह Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) का भी सिग्नेटरी है, जिसका मकसद फाइनेंस से होने वाले उत्सर्जन को मापना और मैनेज करना है।

SEBI ने मुंबई में हुई अपनी 213वीं बोर्ड मीटिंग में बड़े सुधारों की घोषणा की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मार्च 2026 में महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित अपनी 213वीं बोर्ड मीटिंग में कई तरह के रेगुलेटरी बदलावों को मंज़ूरी दी। इन बदलावों में बाज़ार के बिचौलिए, विदेशी निवेशक, वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) और गवर्नेंस के नियम शामिल हैं। सोशल इम्पैक्ट फंड (SIF) के लिए, व्यक्तिगत निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा ₹2 लाख से घटाकर ₹1,000 कर दी गई है। इसके अलावा, बोर्ड ने AIFs को अपनी स्कीम बंद करते समय कुछ खास स्थितियों में (जैसे कि कोई मुक़दमा चल रहा हो, टैक्स की देनदारी हो, या ऑपरेशनल खर्च हों) स्कीम की अवधि खत्म होने के बाद भी लिक्विडेशन से मिली रकम को अपने पास रखने की छूट दी है।

SEBI ने निवेशकों की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए 'वेरिफाइड ऐप लेबल' पहल शुरू की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरमैन, तुहिन कांत पांडे ने मार्च 2026 में 'वेरिफाइड एप्लीकेशन (ऐप) लेबल' पहल शुरू की। इसका मकसद निवेशकों को धोखाधड़ी वाले मोबाइल ऐप्स से बचाना और भारत में सुरक्षित डिजिटल निवेश सुनिश्चित करना है। 66 नकली ट्रेडिंग ऐप्स सहित 1.3 लाख से ज़्यादा धोखाधड़ी वाले निवेश ऐप्स की शिकायतें मिलीं और उन्हें हटा दिया गया। इसी को देखते हुए यह पहल शुरू की गई है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है: "पहले वेरिफाई करें, फिर निवेश करें।" SEBI में रजिस्टर्ड बिचौलियों के ऐप्स Google Play Store पर एक 'वेरिफाइड' बैज दिखाएंगे, जिससे निवेशकों को असली ऐप्स की पहचान करने में आसानी होगी।

HDFC Securities ने ट्रेडर्स के लिए एडवांस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए NxtOption लॉन्च किया। HDFC Bank की सब्सिडियरी, HDFC Securities Limited ने मार्च 2026 में "NxtOption" लॉन्च किया। यह एक अगली पीढ़ी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ही इंटरफ़ेस के ज़रिए Futures & Options (F&O) स्ट्रेटेजीज़ को समझने, बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म यूज़र्स को Straddles, Strangles और Iron Condors जैसी ऑप्शंस स्ट्रेटेजीज़ बनाने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, साथ ही पे-ऑफ चार्ट के ज़रिए रियल-टाइम ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की सुविधा भी देता है। यह Delta, Gamma, Theta, Vega, Implied Volatility (IV) और Open Interest (OI) ट्रेंड्स सहित एडवांस्ड डेरिवेटिव्स एनालिटिक्स प्रदान करता है।

JICA ने भारत में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए ₹16,420 करोड़ के चार ODA लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। Japan International Cooperation Agency (JICA) ने मार्च 2026 में भारत सरकार (GoI) के साथ ₹16,420 करोड़ के Official Development Assistance (ODA) लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इन एग्रीमेंट का मकसद पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड देना है। इन प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र में एक हेल्थकेयर प्रोजेक्ट (जिसे 62,294 मिलियन JPY का समर्थन मिला है), पंजाब में जलवायु-अनुकूल बागवानी (18,684 मिलियन JPY), Bengaluru Metro Rail Project Phase 3 (44.65 km के एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 102,480 मिलियन JPY), और Mumbai Metro Line 11 Project (17.51 km के अंडरग्राउंड कॉरिडोर के लिए 92,400 मिलियन JPY) शामिल हैं।

माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 (CGSMFI-2.0) शुरू की गई। भारत सरकार ने मार्च 2026 में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) को ज़्यादा क्रेडिट प्रवाह की सुविधा देने के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 (CGSMFI-2.0) शुरू की, जो 20 मार्च 2026 से प्रभावी है। यह योजना सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों (MLI) को नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC)-MFI और MFI को दी गई वित्तीय सहायता पर होने वाले संभावित नुकसान के खिलाफ गारंटी कवर देती है; इसका प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) करती है। इस योजना से लगभग 36 लाख उधारकर्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है और यह 30 जून 2026 तक या जब तक ₹20,000 करोड़ के ऋणों की गारंटी नहीं हो जाती, तब तक वैध रहेगी - जो भी पहले हो।

बजट 2025-26 के तहत MSME के लिए आपसी क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) में संशोधन। जनवरी 2025 में शुरू की गई MSME के लिए आपसी क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) को मार्च 2026 में संशोधित किया गया, ताकि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से MSME के लिए क्रेडिट तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सके। यह योजना सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों (MLI) को प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए ₹100 करोड़ तक के ऋणों पर 60% गारंटी कवरेज देती है; इसमें उधारकर्ताओं द्वारा किया गया 5% का शुरुआती योगदान अब चौथे वर्ष से किस्तों में वापस किया जा सकता है, बशर्ते ऋण का प्रदर्शन संतोषजनक हो। ऐसे निर्यातक MSME, जिनका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में टर्नओवर का कम से कम 25% निर्यात से आया हो, वे विशेष प्रावधानों के लिए पात्र हैं, जिसमें ₹20 करोड़ तक की गारंटीकृत ऋण राशि शामिल है।

Lloyd's of London GIFT City में अपना काम शुरू करेगा, जिससे भारत की क्षेत्रीय री-इंश्योरेंस हब के तौर पर भूमिका मज़बूत होगी। Lloyd's of London, जो एक जानी-मानी अंडरराइटिंग मार्केटप्लेस है, मार्च 2026 में GIFT City में अपना काम शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) के साथ मिलकर एक वैधानिक इंश्योरेंस और री-इंश्योरेंस संस्था बनाने की प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर 2025 तक, IFSC इंश्योरेंस ऑफ़िस (IIOs) की संख्या 19 से बढ़कर 24 हो गई, जबकि इंश्योरेंस इंटरमीडियरी ऑफ़िस (IIIOs) की संख्या 25 से बढ़कर 31 हो गई। IIOs और IIIOs द्वारा मिलकर किए गए प्रीमियम का कुल लेन-देन वित्त वर्ष 2025–26 की तीसरी तिमाही में ₹299 मिलियन तक पहुँच गया, जो पिछले साल के ₹148 मिलियन से दोगुने से भी ज़्यादा है।

हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी; 2024–25 में प्रीमियम ₹1.2 लाख करोड़ के पार। भारत का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर लगभग 9% की मज़बूत बढ़ोतरी देख रहा है। 2024–25 में कुल प्रीमियम ₹1.2 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया, जिसकी मुख्य वजह लोगों में बढ़ती जागरूकता और आर्थिक सुरक्षा की बढ़ती माँग है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करने के लिए सख़्त समय-सीमा तय की है: 1 घंटे में प्री-ऑथराइज़ेशन और 3 घंटे में फ़ाइनल ऑथराइज़ेशन। 2024–25 में क्लेम भुगतान अनुपात (क्लेम की संख्या के आधार पर) 87.50% रहा (जो 2022–23 में 66% था)।

NHB ने रक्षा कर्मियों के होम लोन के लिए 'गृह सुगम पोर्टल' लॉन्च किया। नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने 26 मार्च, 2026 को 'गृह सुगम पोर्टल' लॉन्च किया, जिससे रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन तक पहुँच डिजिटल हो गई है। यह पोर्टल प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से बैंक जाए बिना डिजिटल लोन आवेदन करने की सुविधा देता है, जिससे लाभार्थी एक ही आसान इंटरफ़ेस के ज़रिए ऑनलाइन लोन की तुलना कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं; इससे विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में तैनात कर्मियों के लिए पहुँच बेहतर हुई है।

लक्ष्य AMC को म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए SEBI की मंज़ूरी मिली। लक्ष्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) को मार्च 2026 में भारत में म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए SEBI की मंज़ूरी मिली; इसे वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स (NSE और BSE में लिस्टेड कंपनी) ने प्रायोजित किया है। अहमदाबाद, गुजरात में मुख्यालय वाली इस AMC (इस शहर की पहली AMC) ने बेंचमार्क AMC के प्रमुख नेतृत्व को अपने साथ जोड़ा है, जिसमें संजीव शाह, राजन मेहता और संजय गायतोंडे शामिल हैं; इस टीम ने ही Nifty BeES, Gold ETF और Gold BeES जैसे ETF की शुरुआत की थी।

OECD ने FY27 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर 6.1% किया। OECD ने मार्च 2026 में 'Testing Resilience' अंतरिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक अनिश्चितता का हवाला देते हुए FY27 में भारत की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है (जो 6.2% से 10 आधार अंक कम है)। OECD ने यह भी अनुमान लगाया कि भारत FY26 में 7.6% और FY28 में 6.4% की दर से विकास करेगा, जबकि वैश्विक विकास का दृष्टिकोण 2026 के लिए 2.9% ही रहा, लेकिन 2027 के लिए इसे घटाकर 3% कर दिया गया (जो पहले 3.1% था)।

सरकार ने 2026-31 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% पर ही बनाए रखा। भारत सरकार (GoI) ने 5 साल की अवधि (1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक) के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% पर ही अपरिवर्तित रखा है; यह लगातार दूसरी बार है जब लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा RBI के परामर्श से, RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के तहत लिया गया है। इसके अंतर्गत, 'लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' (FIT) ढांचे (जिसे 2016 में लागू किया गया था) के तहत मुद्रास्फीति की ऊपरी सीमा 6% और निचली सीमा 2% निर्धारित की गई है।

Nippon India ETF Gold BeES गोल्ड ETF इनफ्लो के मामले में दुनिया भर में 6वें स्थान पर World Gold Council के अनुसार (28 फरवरी, 2026 तक), Nippon India ETF Gold BeES फंड इनफ्लो के आधार पर दुनिया के शीर्ष 15 गोल्ड ETF में 6वें स्थान पर रहा। इसमें USD 1,085.2 मिलियन (≈6.6 टन सोने की मांग के बराबर) का ज़बरदस्त इनफ्लो हुआ। इस फंड के पास 36.2 टन सोना है, जिससे यह दुनिया के शीर्ष 10 गोल्ड फंड में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय ETF बन गया है; शीर्ष 15 वैश्विक गोल्ड ETF ने मिलकर कुल USD 42.86 बिलियन (≈301.3 टन) का इनफ्लो आकर्षित किया।

Reserve Bank ने Sammaan Capital के Avenir Investment द्वारा अधिग्रहण को मंज़ूरी दी मार्च 2026 में, RBI ने Avenir Investment RSC Limited (Abu Dhabi स्थित International Holding Company PJSC) द्वारा Sammaan Capital Limited (पहले Indiabulls Housing Finance) में नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी। Avenir प्रेफरेंशियल शेयर आवंटन के ज़रिए ₹8,850 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे उसे 41.23% हिस्सेदारी मिलेगी; यदि ओपन ऑफर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाता है, तो यह हिस्सेदारी बढ़कर 63.36% तक पहुँच सकती है, जिससे उसे बहुमत नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा; हालाँकि, SEBI की मंज़ूरी अभी भी लंबित है।

कॉम्पिटिशन कमीशन ने Groww Asset Management में State Street के अधिग्रहण को मंज़ूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मार्च 2026 में Groww Asset Management Limited में State Street Global Advisors Inc. की शेयरहोल्डिंग के अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी। State Street Global Advisors (जो State Street Corporation की एसेट मैनेजमेंट शाखा और सहायक कंपनी है) Billionbrains Garage Ventures के पूर्ण स्वामित्व वाले Groww Mutual Fund में हिस्सेदारी हासिल कर रही है। यह फंड इक्विटी, हाइब्रिड, डेट फंड और ETF सहित कई तरह के निवेश विकल्प देता है।

ASSOCHAM ने FY27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 7% से ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया। ASSOCHAM ने अनुमान लगाया है कि FY27 में भारत की GDP ग्रोथ 7% से ज़्यादा रहेगी। इसकी मुख्य वजह मज़बूत मांग और बढ़ते निवेश हैं। यह अनुमान वैश्विक अनिश्चितताओं और OECD के 6.1% के कम अनुमान के बावजूद भारत की आर्थिक मज़बूती को दिखाता है।

Appointments/Resignations

साउथ इंडियन बैंक ने जोस जोसेफ कट्टूर को पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त किया। साउथ इंडियन बैंक (SIB) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ED) जोस जोसेफ कट्टूर को 23 मार्च, 2026 को नॉन-एग्जीक्यूटिव पार्ट-टाइम चेयरमैन (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) के तौर पर तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया। यह नियुक्ति RBI की मंज़ूरी के बाद, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के नियमों के तहत की गई है। उन्होंने V. J. कुरियन की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 22 मार्च, 2026 को समाप्त हो गया था। जोस जोसेफ कट्टूर के पास सेंट्रल बैंकिंग और फाइनेंशियल रेगुलेशन के क्षेत्र में तीन दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने 1991 से 2023 तक RBI में सेवा दी, जहाँ वे ED के पद से रिटायर हुए और उन्होंने एनफोर्समेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, करेंसी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स जैसे कई अहम विभागों का नेतृत्व किया।

सिटी यूनियन बैंक ने रवींद्र जडेजा को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (CUB) ने मार्च 2026 में भारतीय क्रिकेटर रवींद्रसिंह अनिरुद्धसिंह जडेजा को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया। यह नियुक्ति दो साल की अवधि के लिए मान्य है और इसका ऐलान डिस्क्लोज़र नियमों के तहत की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग के ज़रिए किया गया। इस पहल का मकसद बैंक की पहचान को मज़बूत करना और पूरे भारत में ग्राहकों के एक बड़े वर्ग के साथ जुड़ना है। यह समझौता Baseline Ventures India Private Limited के सहयोग से किया गया, जो खेल जगत की हस्तियों और ब्रांड पार्टनरशिप को मैनेज करती है।

KV रमना मूर्ति SEBI के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त: भारत सरकार ने मार्च 2026 में कोम्पेला वेंकट (K.V.) रमना मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का पूर्णकालिक सदस्य (WTM) नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। K.V. रमना मूर्ति 1991 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय रक्षा लेखा सेवा (IDAS) अधिकारी हैं, जिन्हें सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन का व्यापक अनुभव है; उन्होंने रक्षा मंत्रालय (MoD) के अंतर्गत रक्षा लेखा के अतिरिक्त नियंत्रक महालेखाकार के रूप में कार्य किया है।

CA P.V. नारायण राव ICAI के SRSB के सह-विकल्पित सदस्य नियुक्त (2026-27): चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) P.V. नारायण राव को 23 मार्च 2026 को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के 'सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड' (SRSB) का सह-विकल्पित सदस्य नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 2026-27 की अवधि के लिए की गई है। एक सह-विकल्पित सदस्य के रूप में, वे भारत में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मानकों के विकास और सुदृढ़ीकरण में योगदान देंगे। गौरतलब है कि ICAI के SRSB की स्थापना फरवरी 2020 में वैश्विक स्तर पर संरेखित सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क और रिपोर्टिंग मानकों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।

UNIQLO ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। UNIQLO ने मार्च 2026 में भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो खेल और लाइफस्टाइल फैशन के बीच एक रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है। यह साझेदारी UNIQLO की 'LifeWear' फिलॉसफी के अनुरूप है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए डिज़ाइन किए गए सरल, उच्च-गुणवत्ता वाले, आरामदायक और व्यावहारिक कपड़ों पर केंद्रित है; इस अभियान में विशेष रूप से AIRism कलेक्शन, और उसमें भी AIRism Oversized T-shirt को प्रमुखता से दिखाया गया है।

Yamaha Music India ने A.R. Rahman को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मार्च 2026 में A.R. Rahman को Yamaha Music India Private Limited का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। Yamaha Music India, जापान की Yamaha Corporation की भारतीय सहायक कंपनी है, जो वाद्य यंत्रों और पेशेवर ऑडियो उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत है; इसके अलावा, कंपनी का एक विनिर्माण संयंत्र चेन्नई में, एक कॉर्पोरेट कार्यालय गुरुग्राम में और एक अनुभव केंद्र (Experience Centre) बेंगलुरु में स्थित है।

बालेंद्र शाह 35 साल की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता और पूर्व रैपर बालेंद्र शाह (35) ने 27 मार्च, 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने सुशीला कार्की (अंतरिम प्रधानमंत्री) की जगह ली। 5 मार्च, 2026 को हुए चुनावों में उनकी पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीतीं। इस तरह, 138 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए, उन्होंने नेपाल के संघीय ढांचे के तहत पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई।

साध्वी निरंजन ज्योति ने NCBC के अध्यक्ष का पद संभाला। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले) साध्वी निरंजन ज्योति ने मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

किरण उमेश महाले NCBC की सदस्य नियुक्त हुईं। अमरावती नगर निगम की पूर्व महापौर श्रीमती किरण उमेश महाले को मार्च 2026 में NCBC का सदस्य नियुक्त किया गया। सहकारी और सामाजिक संस्थाओं में अपने पिछले कार्यों के अनुभव के आधार पर, वे सुशासन, महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर के विकास से जुड़ा अपना मजबूत अनुभव इस पद पर लेकर आई हैं।

Defence News

भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया में 'अभ्यास काकाडू 2026' में भाग लेती है। भारतीय नौसेना का एक फ्रिगेट, भारतीय नौसेना का जहाज (INS) नीलगिरि, मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया में 'अभ्यास काकाडू 2026' के समुद्री चरण में शामिल हुआ। यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में उसकी तैनाती का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। अभ्यास काकाडू 2026 के 17वें संस्करण में 19 से अधिक देशों और 6,000 कर्मियों ने भाग लिया। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के जर्विस बे से डार्विन तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। 21 मार्च 2026 को सिडनी हार्बर में 'काकाडू फ्लीट रिव्यू' आयोजित किया गया, जो एक दशक से अधिक समय में विदेशी युद्धपोतों का सबसे बड़ा जमावड़ा था और इसने RAN की 125वीं वर्षगांठ को भी चिह्नित किया। INS नीलगिरि के चालक दल ने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हार्बर चरण के दौरान आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में 'काकाडू शील्ड ट्रॉफी' जीती।

भारतीय नौसेना उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट 'तारागिरी' (F41) को कमीशन करेगी। भारतीय नौसेना 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में अपने नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट, तारागिरी (F41) को कमीशन करने के लिए तैयार है। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। तारागिरी (F41) 'प्रोजेक्ट 17A' श्रेणी का चौथा जहाज है और इसका वज़न 6,670 टन है। इसे मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा बनाया गया है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी रही है। यह जहाज विश्व स्तरीय हथियार प्रणाली से लैस है, जिसमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) प्रणाली शामिल हैं। इन सभी को एक अत्याधुनिक 'कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम' (CMS) के माध्यम से एकीकृत किया गया है।

भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में 'अमोघ ज्वाला' अभ्यास किया। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने 6 से 18 मार्च, 2026 तक उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में 'अमोघ ज्वाला' अभ्यास किया। यह 13-दिवसीय सैन्य अभ्यास था जिसका उद्देश्य बहु-डोमेन परिचालन वातावरण में मशीनीकृत युद्ध के लिए भारतीय सेना की तैयारियों को परखना था। इस अभ्यास में अटैक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन प्रणालियों का उपयोग करके उच्च-गति वाले मशीनीकृत अभियानों का प्रदर्शन किया गया। इसकी मुख्य विशेषताओं में नेटवर्क-सक्षम युद्धक्षेत्र प्लेटफार्मों के साथ-साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की तैनाती शामिल थी। सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज ने सैनिकों के पेशेवरपन, परिचालन उत्कृष्टता और युद्ध की तत्परता की सराहना की। उन्होंने प्रौद्योगिकी-आत्मसातीकरण, संयुक्तता और थल, वायु, साइबर, अंतरिक्ष तथा ISR (खुफिया, निगरानी और टोही) क्षमताओं के एकीकरण के महत्व पर भी जोर दिया।

रक्षा मंत्रालय ने ₹858 करोड़ के रक्षा खरीद सौदों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में ₹858 करोड़ के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए: (1) JSC रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (रूस) के साथ ₹445 करोड़ का अनुबंध, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए 'तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली' खरीदी जाएगी। यह प्रणाली विमानों, ड्रोनों और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ बहु-स्तरीय वायु रक्षा को मजबूत करेगी; (2) बोइंग इंडिया डिफेंस के साथ ₹413 करोड़ का अनुबंध, जिसके तहत 'P-8I समुद्री टोही विमान' का डिपो-स्तरीय निरीक्षण किया जाएगा। यह अनुबंध 'बाय इंडियन' (Buy Indian) श्रेणी के अंतर्गत आता है (जिसमें 100% स्वदेशी सामग्री शामिल है), और यह देश के भीतर ही MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल) सुविधा को सक्षम बनाता है, जिससे विदेशी निर्भरता कम होती है।

'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' रणनीतिक जलक्षेत्रों में ऊर्जा जहाज़ों की सुरक्षा करता है। भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' के तहत 5 से ज़्यादा अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत तैनात किए, ताकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रणनीतिक मार्ग से गुज़रने वाले भारत आने वाले 22 ऊर्जा जहाज़ों को सुरक्षा दी जा सके; इनमें LNG, LPG और कच्चे तेल से भरे 20 प्राथमिकता वाले जहाज़ शामिल थे। पाइन गैस, जग वसंत, शिवालिक, नंदा देवी और जग लाडकी जहाज़ों को सफलतापूर्वक सुरक्षा दी गई, जिससे भारत के ऊर्जा सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मज़बूती मिली।

'प्रोजेक्ट वायु बाण' भारत का पहला हेलीकॉप्टर-लॉन्च ड्रोन विकसित करता है। भारतीय वायु सेना के एयरोस्पेस डिज़ाइन निदेशालय (DAD) ने मार्च 2026 में 'वायु बाण' प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके तहत घरेलू विक्रेताओं से एक ऐसे स्वायत्त हेलीकॉप्टर-लॉन्च UAS के लिए 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' (RFP) जारी किया गया, जिसे 50 किलोमीटर से ज़्यादा की सुरक्षित दूरी (स्टैंड-ऑफ डिस्टेंस) से तैनात किया जा सकता है, जिससे हवाई चालक दल MANPADS की मारक सीमा से सुरक्षित रहते हैं। इस हेलीकॉप्टर-ड्रोन क्षमता के साथ भारत, USA और चीन के बाद ऐसा तीसरा देश बन गया है।

भारतीय सेना-IITM प्रवर्तक साझेदारी ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की गति बढ़ाई। भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर (EME) ने मार्च 2026 में IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज़ फाउंडेशन के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चेन्नई के अवाडी में एक नोडल स्वदेशीकरण केंद्र (NIC) स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य उपकरणों से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना, प्रोटोटाइप विकसित करना और उनके डिप्लॉयमेंट में सहायता करना है। यह साझेदारी तमिलनाडु रक्षा गलियारे (TNDC) का लाभ उठाते हुए सेंसिंग, साइबर-फिजिकल सिस्टम (CPS) और स्वायत्त प्रौद्योगिकियों (AT) पर केंद्रित है।

Awards and Recognitions

भारतीय पर्वतारोही भूपतिराजू अनमिश वर्मा ने सात ज्वालामुखी चोटियों के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के रहने वाले भूपतिराजू अनमिश वर्मा ने मार्च 2026 में सात ज्वालामुखी चोटियों (पुरुष वर्ग में) पर सबसे तेज़ी से चढ़ने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड (GWR) बनाया। उन्होंने यह चुनौती 92 दिन, 4 घंटे और 45 मिनट में पूरी की, और पिछले वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना अभियान 23 अक्टूबर, 2024 को दक्षिण-पश्चिम रूस में माउंट एल्ब्रस (यूरोप) से शुरू किया, और 23 जनवरी, 2025 को अंटार्कटिका में माउंट सिडली पर समाप्त किया। इस रिकॉर्ड को 6 फरवरी, 2026 को आधिकारिक मान्यता मिली, और उन्हें 17 मार्च, 2026 को दिल्ली में अपना प्रमाणपत्र मिला।

रितुपर्णा सेनगुप्ता को UK के हाउस ऑफ़ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विजेता भारतीय अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता को मार्च 2026 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ़ कॉमन्स (ब्रिटिश संसद) में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर GloWomen CiC (UK स्थित एक पंजीकृत सामुदायिक हित कंपनी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान की मान्यता के तौर पर दिया गया। वह राजकाहिनी (2015), आहा रे (2019), और पार्सल (2020) जैसी फ़िल्मों के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं, और उन्होंने रितुपर्णो घोष की फ़िल्म दहन (1998) में अपनी भूमिका के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' श्रेणी में राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार जीता था।

BRICS CCI WE समिट 2026 में कल्पना सोरेन को 'महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेज़र पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। झारखंड के गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन को मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित BRICS CCI WE वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन और सम्मान समारोह 2026 के दौरान 'महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेज़र पुरस्कार 2026' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया, विशेष रूप से झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक को SHG-बैंक लिंकेज 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने मार्च 2026 में कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KGB) को 'स्वयं सहायता समूहों (SHG)-बैंक लिंकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (MoRD) ने तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित 'वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन' और '25वीं केंद्रीय स्तरीय समन्वय समिति (CLCC) की बैठक' के दौरान KGB की महाप्रबंधक (GM) वी. एम. रुक्मिणी देवी को यह पुरस्कार प्रदान किया। KGB ने दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) से जुड़े 80,904 SHGs को ₹2,835 करोड़ का ऋण प्रदान किया है।

कावेह मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 का विजेता घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक कावेह मदानी को मार्च 2026 में, फ्रांस के पेरिस में UNESCO मुख्यालय में आयोजित विश्व जल दिवस (22 मार्च) कार्यक्रम के दौरान, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 का विजेता घोषित किया गया। 44 वर्ष की आयु में, वे स्टॉकहोम जल पुरस्कार के 35 वर्षों के इतिहास में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए; साथ ही, वे यह पुरस्कार पाने वाले संयुक्त राष्ट्र के पहले अधिकारी और पहले पूर्व राजनेता भी बने।

नटराजन चंद्रशेखरन को 'ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एम्पायर' के मानद नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया। टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को मार्च 2026 में, यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा 'ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एम्पायर' के मानद नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया; इसे चार्ल्स तृतीय की ओर से लिंडी कैमरन ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर प्रदान किया।

नंदामुरी बालकृष्ण को IFFD 2026 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अनुभवी तेलुगू अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण को 26 मार्च को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके 50 वर्षों के योगदान को देखते हुए दिया गया। यह अवार्ड भारत मंडपम में रेखा गुप्ता द्वारा प्रदान किया गया; उनकी फिल्म 'भगवंत केसरी' (अनिल रविपुडी द्वारा निर्देशित) ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ तेलुगू फिल्म का पुरस्कार जीता, और उन्हें पद्म भूषण (2025) से भी सम्मानित किया गया।

शबाना आज़मी को BRICS CCI WE ट्रेलब्लेज़र अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनुभवी अभिनेत्री शबाना आज़मी को नई दिल्ली में आयोजित 6वें BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स महिला सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन (21-23 मार्च, 2026) में BRICS CCI WE ट्रेलब्लेज़र: लिविंग लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें "भारतीय सिनेमा में 50 वर्षों की उत्कृष्टता" के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक उत्कृष्टता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मीनाक्षी लेखी ने 'मिशन शक्तिसैट' पहल का अनावरण किया। विदेश मंत्रालय की पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और 'मिशन शक्तिसैट' की ग्लोबल चेयर मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में आयोजित 6वें BRICS CCI WE शिखर सम्मेलन (21-23 मार्च, 2026) में इस पहल का अनावरण किया। इस पहल का उद्देश्य BRICS देशों में अंतरिक्ष, विज्ञान और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

Summits and Conferences News

नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन; कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट (BES 2026) का पहला संस्करण 19-22 मार्च, 2026 तक नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित किया गया। इस समिट में भारत के ऊर्जा संक्रमण और बिजली क्षेत्र में सुधारों को मज़बूत करने के लिए दुनिया भर के हितधारक एक साथ आए। इस समिट का उद्घाटन केंद्रीय बिजली मंत्री (MoP) मनोहर लाल ने किया, जिसकी थीम थी "Electrifying Growth. Empowering Sustainability. Connecting Globally." इस कार्यक्रम के दौरान इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल (www.indiancarbonmarket.gov.in) लॉन्च किया गया। यह पोर्टल कार्बन मार्केट को लागू करने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में काम करेगा। इस समिट का अगला संस्करण (BES 2028) गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा।

नई दिल्ली में आयोजित BRICS CCI WE शिखर सम्मेलन 2026 का अवलोकन। BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन एम्पावरमेंट (BRICS CCI WE) शिखर सम्मेलन का छठा संस्करण 21 से 23 मार्च, 2026 तक नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित किया गया। 2026 के शिखर सम्मेलन का विषय था "नवाचार, विज्ञान नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता में महिलाएं (WISE) – बदलाव की प्रेरणा, कल का निर्माण," जिसका आयोजन BRICS CCI WE वर्टिकल द्वारा BRICS वीमेन बिजनेस एलायंस (BRICS WBA) के सहयोग से किया गया था। इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण 'मिशन शक्तिसैट' (Mission ShakthiSAT) का अनावरण था, जिसे विदेश मामलों की पूर्व राज्य मंत्री और इस पहल की ग्लोबल चेयर, मीनाक्षी लेखी ने प्रस्तुत किया।

भारत ने WTO के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए प्रस्ताव पेश किए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जो 26 से 29 मार्च, 2026 तक याउंडे, कैमरून में आयोजित होने वाला है। इन प्रस्तावों का मुख्य फोकस खाद्य सुरक्षा और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका पर है। WTO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता कैमरून के व्यापार मंत्री, ल्यूक मैग्लोयर मबार्गा अटांगा करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र जनवरी 2027 में न्यूयॉर्क में पहले 'हाई सीज़ समिट' की मेज़बानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र (UN) जनवरी 2027 में न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय में अब तक के पहले 'हाई सीज़ समिट' (High Seas Summit) की मेज़बानी करेगा। यह समिट जून 2023 में अपनाई गई 'हाई सीज़ संधि' (राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता – BBNJ) पर आधारित होगा। 'हाई सीज़ समिट' (पार्टियों का सम्मेलन – COP) 11 से 22 जनवरी, 2027 तक आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य संधि के कार्यान्वयन तंत्र और संस्थागत ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना है, साथ ही जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी उन चुनौतियों का समाधान करना है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बनी हुई हैं।

नई दिल्ली में 6वां BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स महिला सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला सशक्तिकरण (BRICS CCI WE) का 6वां शिखर सम्मेलन 21-23 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में "नवाचार, विज्ञान नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता में महिलाएं (WISE) – बदलाव की प्रेरणा, कल का निर्माण" विषय के साथ आयोजित किया गया। BRICS महिला व्यापार गठबंधन (BRICS WBA) के सहयोग से BRICS CCI WE वर्टिकल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य BRICS देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) में विज्ञान, नवाचार, नेतृत्व और उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना था।

भारत को फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 के लिए आमंत्रित किया गया। भारत को 15-17 जून को फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में एक प्रमुख भागीदार देश के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आमंत्रण वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

कैमरून में WTO MC14 की शुरुआत। WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) 26 मार्च, 2026 को कैमरून के याउंडे में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में 160 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वैश्विक व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

Ranks and Reports

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026: पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित; भारत 13वें स्थान पर। मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (IEP) द्वारा जारी 'ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स' (GTI) 2026 ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश के रूप में 8.574 के कुल स्कोर के साथ शीर्ष पर रखा गया है; 2025 में यहाँ 1,139 मौतें और 1,045 आतंकवादी घटनाएँ दर्ज की गईं (जो 2013 के बाद से मौतों का सबसे उच्च स्तर है)। भारत 6.428 के कुल स्कोर के साथ 13वें स्थान पर रहा, जिसके बाद अफगानिस्तान (11वें स्थान पर) 6.678 के स्कोर के साथ रहा। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2025 में आतंकवादी घटनाएँ 2020 की तुलना में लगभग छह गुना अधिक थीं, जबकि आतंकवाद से संबंधित मौतों में 28% की कमी आई और यह घटकर 5,582 रह गईं; वहीं घटनाओं में 22% की कमी आई और यह घटकर 2,944 रह गईं, जो 2007 के बाद से सबसे कम आँकड़े हैं।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026: IIT (ISM) धनबाद और IIM अहमदाबाद भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहे। मार्च 2026 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 के 16वें संस्करण में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी – इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (IIT-ISM) धनबाद, झारखंड को इंजीनियरिंग – मिनरल और माइनिंग में वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान मिला। वहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद, गुजरात ने बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज, और मार्केटिंग—दोनों ही विषयों में 21वां स्थान हासिल किया; इसके साथ ही मार्केटिंग विषय की रैंकिंग में भारत की पहली बार एंट्री हुई है। अब भारत के 99 संस्थान (2025 के 79 संस्थानों से बढ़कर) 599 विषय प्रविष्टियों के साथ इस सूची में शामिल हैं। भारत ने 2024 के बाद से शीर्ष-50 विषयों में अपनी उपस्थिति दोगुनी कर ली है, और 12 संस्थानों में कुल 27 स्थान हासिल किए हैं। वैश्विक स्तर पर USA 228 संस्थानों और 37 विषयों में प्रथम स्थान के साथ सबसे आगे है, जबकि प्रविष्टियों की संख्या के आधार पर भारत चौथा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र बन गया है।

विश्व व्यापार संगठन का व्यापार दृष्टिकोण 2026: वैश्विक माल व्यापार वृद्धि घटकर 1.9% होने की उम्मीद। विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने मार्च 2026 में अपना 'वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण और सांख्यिकी – मार्च 2026' जारी किया, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2026 में वैश्विक माल व्यापार वृद्धि तेज़ी से घटकर 1.9% रह जाएगी, जो 2025 में 6% थी। इस गिरावट का कारण पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, AI से संबंधित मांग का सामान्य होना, और टैरिफ के कारण शिपमेंट की अग्रिम लोडिंग (front-loading) है; वहीं, 2027 में वैश्विक माल व्यापार वृद्धि के फिर से बढ़कर 2.6% होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में वृद्धि 2025 के 3% से घटकर 2026 में 4.8% होने की उम्मीद है, जिसके बाद 2027 में यह बढ़कर 5.1% हो जाएगी; जबकि वैश्विक GDP वृद्धि 2025 के 9% से थोड़ी कम होकर 2026 और 2027 में 2.8% रहने का अनुमान है।

हुरुन रिपोर्ट 2026: दुनिया भर में खुद से बनी महिला अरबपतियों की संख्या रिकॉर्ड 150 तक पहुंची। मार्च 2026 में जारी हुरुन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, दुनिया भर में खुद से बनी महिला अरबपतियों की संख्या 150 तक पहुंच गई है, और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर $470 बिलियन हो गई है। पिछले एक दशक में यह संख्या दोगुनी होकर 75 से 150 हो गई है, जो दुनिया भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमशीलता में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है; पिछले तीन वर्षों में कुल संपत्ति में 52% की वृद्धि हुई है और 2026 में 60 नई महिलाएं इस सूची में शामिल हुई हैं। चीन 78 खुद से बनी महिला अरबपतियों के साथ दुनिया में पहले स्थान पर रहा, जो कुल संख्या का आधे से अधिक है; इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) 40 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें डायने हेंड्रिक्स $24 बिलियन की संपत्ति के साथ सूची में शीर्ष पर रहीं।

भारत की खेल अर्थव्यवस्था 2025 में $2 बिलियन का आंकड़ा पार कर गई: ₹18,864 करोड़ तक पहुंची। मार्च 2026 में जारी WPP मीडिया की 'स्पोर्टिंग नेशन: बिल्डिंग ए लेगेसी' नामक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की खेल अर्थव्यवस्था ने 2025 में $2 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, और ₹18,864 करोड़ ($2.13 बिलियन) तक पहुंच गई। इस क्षेत्र ने 2024 के ₹16,633 करोड़ की तुलना में 4% की सालाना वृद्धि दर्ज की, जिसमें मीडिया पर होने वाला खर्च सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, जो 2025 में कुल बाजार का 51% था। क्रिकेट ने भारत की खेल अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा बनाए रखा, और 2025 में ₹16,704 करोड़ (कुल बाजार का लगभग 89%) का योगदान दिया।

फरवरी 2026 में चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना। फरवरी 2026 में चीन, नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया। इस महीने भारत का चीन को निर्यात 32.4% बढ़कर 1.67 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इस महीने के दौरान भारत का कुल निर्यात साल-दर-साल आधार पर 0.81% की मामूली गिरावट के साथ 36.61 अरब अमेरिकी डॉलर रहा; हालाँकि, इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पादों की शिपमेंट में वृद्धि के कारण निर्यात में बढ़त देखने को मिली।

OECD अंतरिम रिपोर्ट: भारत की FY27 विकास दर संशोधित होकर 6.1% हुई। 'Testing Resilience' (लचीलेपन की परख) शीर्षक वाली OECD आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट (मार्च 2026) में, वैश्विक अनिश्चितता का हवाला देते हुए, भारत की GDP विकास दर FY27 के लिए 6.1% (6.2% से 10 आधार अंक कम) रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही, FY26 के लिए 7.6% और FY28 के लिए 6.4% विकास दर का अनुमान व्यक्त किया गया है। वैश्विक विकास का परिदृश्य 2026 के लिए 2.9% पर स्थिर रहा, लेकिन 2027 के लिए इसे 3.1% से घटाकर 3% कर दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रैंकिंग में सबसे ऊपर: मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे (2-8 मार्च, 2026) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% अप्रूवल रेटिंग और 26% डिसअप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर के तौर पर पहले स्थान पर रहे। उन्होंने स्विट्जरलैंड के गाय पारमेलिन (62%) और दक्षिण कोरिया के ली जे-म्युंग (62%) को पीछे छोड़ दिया। वहीं, प्रमुख ग्लोबल लीडर्स में डोनाल्ड ट्रंप (39%), कीर स्टारमर (24%), फ्रेडरिक मर्ज़ (20%) और इमैनुएल मैक्रॉन (17%) उनसे नीचे रहे।

Nippon India ETF Gold BeES गोल्ड ETF इनफ्लो के मामले में दुनिया भर में छठे स्थान पर: Nippon India ETF Gold BeES ने फंड इनफ्लो के आधार पर (वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, 28 फरवरी, 2026) दुनिया के शीर्ष 15 गोल्ड ETFs में छठा स्थान हासिल किया। इसमें 1,085.2 मिलियन USD (≈6.6 टन) का इनफ्लो हुआ और इसके पास 36.2 टन सोना मौजूद है; यह दुनिया के शीर्ष 10 गोल्ड फंड रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय ETF है।

Sports News

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में 25 मार्च 2026 से शुरू होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किए जाएंगे, जिनकी मेज़बानी रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा करेंगे। इन खेलों में देश भर से लगभग 2,300 एथलीटों सहित 6,000 से अधिक प्रतिभागी एक साथ आएंगे। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना और स्वदेशी खेल परंपराओं को संरक्षित करना है। छत्तीसगढ़ को इसकी मज़बूत आदिवासी सांस्कृतिक विरासत और 32% से अधिक आदिवासी आबादी की मौजूदगी के कारण मेज़बान राज्य के रूप में चुना गया था। इन खेलों में तीरंदाज़ी, एथलेटिक्स, फ़ुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती जैसे प्रमुख खेल शामिल होंगे, साथ ही मल्लखंभ और कबड्डी जैसे स्वदेशी खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

लेब्रोन जेम्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के रेगुलर सीज़न में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। लेब्रोन जेम्स मार्च 2026 में ऑरलैंडो मैजिक के ख़िलाफ़ लॉस एंजिल्स लेकर्स के लिए अपना 1,612वां मैच खेलकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के रेगुलर सीज़न में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 1997 से रॉबर्ट पैरिश के नाम दर्ज 1,611 मैचों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 41 साल की उम्र में 23 सीज़न में यह उपलब्धि हासिल की, जो पेशेवर बास्केटबॉल में उनकी असाधारण लंबी पारी, मज़बूती और निरंतरता को दर्शाता है। लॉस एंजिल्स लेकर्स ने ऑरलैंडो मैजिक पर 105-104 से जीत हासिल की, जिसमें ल्यूक केनार्ड ने मैच के आख़िरी पलों में (बज़र-बीटिंग) एक थ्री-पॉइंटर स्कोर किया, जिससे लेकर्स की जीत का सिलसिला नौ मैचों तक पहुँच गया।

अरुंधति रेड्डी को फरवरी 2026 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 'महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ' चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्वेंटी20 इंटरनेशनल सीरीज़ में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए अरुंधति रेड्डी को फरवरी 2026 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 'महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ' चुना गया। वह इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी रहीं; उन्होंने 3 मैचों में 10.87 की बॉलिंग औसत और 7.25 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट लिए। सिडनी में उन्होंने अपने करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर 4 विकेट लिए। यह उनका पहला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 'प्लेयर ऑफ़ द मंथ' अवॉर्ड है।

साहिबज़ादा फरहान को फरवरी 2026 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 'पुरुष प्लेयर ऑफ़ द मंथ' चुना गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पुरुष ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद साहिबज़ादा फरहान को फरवरी 2026 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 'पुरुष प्लेयर ऑफ़ द मंथ' चुना गया। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे; उन्होंने 7 मैचों में 76.60 की औसत और 160.25 के स्ट्राइक रेट से 383 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने ICC पुरुष ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप के किसी एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, और इस टूर्नामेंट के किसी एक सीज़न में दो शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज़ बन गए।

भारत भुवनेश्वर, ओडिशा में 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। भारत ने 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। यह पहली बार होगा जब देश इस प्रतिष्ठित इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। यह चैंपियनशिप भुवनेश्वर, ओडिशा के कलिंग इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस घोषणा को विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को ने किया। इसके साथ ही भारत उन एशियाई देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने पहले इस चैंपियनशिप की मेज़बानी की है; इन देशों में जापान, कतर और चीन शामिल हैं।

भारत ने एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में दो कांस्य पदक जीते और कई फाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत ने मार्च 2026 में आयोजित एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 के टीम इवेंट्स में दो कांस्य पदक जीते। रूमा बिस्वास, कीर्ति और रिधि फोर की महिला रिकर्व टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कांस्य पदक जीता, जबकि रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय कंबोज की पुरुष कंपाउंड टीम ने भूटान को 234-232 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय तीरंदाज़ों ने कई फाइनल मुकाबलों में भी अपनी जगह पक्की कर ली है, जिससे आने वाले मैचों में पदकों की मज़बूत संभावनाएँ बन गई हैं।

कैरोलिना मारिन ने 32 साल की उम्र में प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। स्पेनिश ओलंपिक और विश्व बैडमिंटन चैंपियन कैरोलिना मारिया मारिन मार्टिन ने मार्च 2026 में, 32 साल की उम्र में, घुटने की तीसरी गंभीर चोट से उबर न पाने के कारण संन्यास की घोषणा की। उन्होंने रिकॉर्ड 66 हफ़्तों तक विश्व नंबर एक रैंकिंग हासिल की, ओलंपिक स्वर्ण पदक (रियो 2016) जीता - ऐसा करने वाली वह सिंगल्स बैडमिंटन में पहली गैर-एशियाई महिला बनीं - और 3 विश्व चैंपियनशिप (2014, 2015, 2018) जीतीं, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गईं।

IOC ने 2028 ओलंपिक के लिए नई महिला श्रेणी सुरक्षा नीति को मंज़ूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने मार्च 2026 में 'ओलंपिक खेलों में महिला (Women's) श्रेणी की सुरक्षा' नीति को मंज़ूरी दी, जो LA28 ओलंपिक (14-30 जुलाई, 2028) से प्रभावी होगी। इस नीति के तहत महिला श्रेणी में पात्रता के लिए SRY-नेगेटिव परीक्षण अनिवार्य है; SRY-पॉजिटिव एथलीट - जिनमें XY ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं - महिला स्पर्धाओं के लिए अयोग्य माने जाएँगे, सिवाय CAIS मामलों और कुछ ऐसे DSD मामलों के जिनमें टेस्टोस्टेरोन का कोई अतिरिक्त लाभ न हो। इस नीति के तहत लार/गाल के स्वैब/रक्त के नमूने का उपयोग करके "जीवन में एक बार होने वाला लिंग परीक्षण" लागू किया जाएगा।

Schemes and Committees News

DoT ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2026 लॉन्च किया। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने मार्च 2026 में '5G इनोवेशन हैकाथॉन 2026' लॉन्च किया। यह '100 5G यूज़ केस लैब्स प्रोग्राम' के तहत उनकी मुख्य पहल का दूसरा संस्करण है। इसका मकसद 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वदेशी और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देना है। यह हैकाथॉन पूरे भारत के छात्रों, स्टार्ट-अप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्वतंत्र इनोवेटर्स के लिए खुला था। यह 20 मार्च से 17 अप्रैल 2026 तक चला, और इसके अंतिम नतीजे 1 अक्टूबर 2026 को घोषित किए गए। इस हैकाथॉन में ₹10 लाख से ज़्यादा का कुल इनाम रखा गया था। इसमें पहले इनाम के लिए ₹5,00,000, दूसरे इनाम के लिए ₹3,00,000 और तीसरे इनाम के लिए ₹1,50,000 शामिल थे। इसके अलावा, 'बेस्ट आइडिया' के लिए ₹50,000 का इनाम और 25 टीमों तक को IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) में मदद देने का भी प्रावधान था।

MoRD ने शासन और निगरानी में क्रांति लाने के लिए रियल-टाइम आंतरिक ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने मार्च 2026 में एक व्यापक 'आंतरिक ऑडिट पोर्टल' के शुरू होने की घोषणा की। इसका मकसद पारंपरिक मैन्युअल ऑडिट प्रक्रियाओं से हटकर एक रियल-टाइम, केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ना है। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने विकसित किया है। इसमें सचिव-स्तर तक पहुँच की सुविधा है, जिससे विभिन्न विभागों में ऑडिट के प्रदर्शन की सीधी निगरानी की जा सकती है और वरिष्ठ नेतृत्व को प्रशासनिक बाधाओं की पहचान करने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि यह पोर्टल ऑडिट से जुड़ी टिप्पणियों के समाधान की गति को बढ़ाकर 'अनुपालन अंतर' (compliance gap) को कम करेगा।

NITI आयोग ने कौशल विकास और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए RISE सेंटर को ₹1.55 करोड़ मंज़ूर किए। भारत को बदलने वाली राष्ट्रीय संस्था (NITI आयोग) ने मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश (AP) के NTR ज़िले के इब्राहिमपटनम मंडल में गुंटुपल्ली स्थित ग्रामीण इन्क्यूबेशन, कौशल और उद्यमिता (RISE) सेंटर के कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर ₹1.55 करोड़ मंज़ूर किए। इस मंज़ूर वित्तीय सहायता का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और AI-आधारित कौशल सर्वेक्षण, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को उद्यमी बनने में मदद करना है। अब तक 1,000 से ज़्यादा महिलाओं को AI, स्पोकन इंग्लिश, पेपर क्राफ़्ट और सोलर पैनल लगाने जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा चुका है, और 300 से ज़्यादा परिवारों ने अपने छोटे उद्यम शुरू कर दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय AI कौशल पहल, My WAVES और इन-बिल्ट TV ट्यूनर लॉन्च किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2026 में तीन बड़ी पहलें लॉन्च कीं: राष्ट्रीय AI कौशल पहल, MyWAVES, और टेलीविज़न (TV) सेट में इन-बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर के साथ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (EPG)। राष्ट्रीय AI कौशल कार्यक्रम Google और YouTube के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ (IICT) के ज़रिए रचनात्मक और मीडिया क्षेत्रों के 15,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। WAVES OTT प्लेटफ़ॉर्म के भीतर एक नई सुविधा के रूप में पेश किया गया MyWAVES नागरिकों को सामग्री बनाने, अपलोड करने और साझा करने की अनुमति देता है, जबकि उन्नत EPG और इन-बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर दर्शकों को बिना किसी अलग सेट-टॉप बॉक्स की ज़रूरत के सीधे TV सेट पर DD Free Dish चैनल देखने में सक्षम बनाता है।

MoE ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' को पूरे देश में लागू करने के लिए 3 साल का एक्शन प्लान जारी किया। मार्च 2026 में, शिक्षा मंत्रालय (MoE) के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSL) के सचिव और गृह मंत्रालय (MHA) के गृह सचिव की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के मुख्य सचिवों को एक संयुक्त एडवाइज़री जारी की गई। इस एडवाइज़री का मकसद स्कूलों में 'नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) एक्शन प्लान' को मिशन-मोड में लागू करना था। इस राष्ट्रीय पहल का लक्ष्य एक नशा-मुक्त भारत बनाना है। इसका मुख्य ज़ोर छात्रों के बीच नशे की लत को रोकना और स्कूलों में नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्लान के मुख्य प्रावधानों में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे को 'नशा-मुक्त क्षेत्र' घोषित करना और स्कूल प्रमुखों या नोडल शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य करना शामिल है कि वे किसी भी उल्लंघन की सूचना स्थानीय अधिकारियों को दें।

सरकार ने PM इंटर्नशिप योजना 2026 में बदलाव किए: दायरा बढ़ाया, पात्रता आसान की और स्टाइपेंड बढ़ाया। सरकार ने मार्च 2026 में PM इंटर्नशिप योजना में बदलाव किए ताकि इसमें ज़्यादा लोग हिस्सा ले सकें और इसके नतीजे बेहतर हों। इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs) जैसे नए ज़माने के सेक्टर को भी शामिल किया गया है। एक बड़ा सुधार यह था कि कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) की शर्त हटा दी गई, जिससे अब सभी कंपनियाँ इसमें हिस्सा ले सकती हैं। पात्रता के नियमों में भी ढील दी गई, जिससे अब पोस्टग्रेजुएट और MBA ग्रेजुएट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई और अधिकतम उम्र 24 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी गई। हर महीने मिलने वाला स्टाइपेंड ₹5,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया गया है। अभी इस योजना का तीसरा चरण चल रहा है, जिसका लक्ष्य 1 लाख (100,000) इंटर्नशिप के मौके उपलब्ध कराना है।

संसद में 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2026' पेश किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद, मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2026' पेश किया। इस विधेयक में 23 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 79 केंद्रीय कानूनों में 784 संशोधनों का प्रस्ताव है। यह विधेयक 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और 'जीवन की सुगमता' (Ease of Living) को बढ़ावा देने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन करता है। इसके तहत कारावास की सज़ा को मौद्रिक दंड या चेतावनी से बदला गया है, चरणबद्ध प्रवर्तन (graded enforcement) की व्यवस्था शुरू की गई है, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए विवादों के त्वरित समाधान के लिए 'निर्णायक अधिकारियों' (Adjudicating Officers) तथा 'अपीलीय प्राधिकारियों' (Appellate Authorities) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

'पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना' संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। सरकार 'पोषक तत्व आधारित सब्सिडी' (NBS) योजना को बढ़ावा देती है, जिसके तहत उर्वरकों में मौजूद नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटेशियम (K) और सल्फर (S) की मात्रा के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, सरकार ने ₹1,77,129.50 करोड़ का आवंटन किया, जिससे रियायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी। खपत के रुझान दर्शाते हैं कि DAP की खपत घटकर 96.29 LMT रह गई है, जबकि NPKS की खपत बढ़कर 149.72 LMT तक पहुँच गई है। इसके अलावा, नैनो यूरिया की कुल बिक्री 201.14 लाख बोतलों (फरवरी 2026 तक) तक पहुँच गई है, जो किसानों द्वारा इसके बढ़ते उपयोग और स्वीकार्यता को दर्शाता है।

उर्वरक विभाग ने DBT सिस्टम के सफल कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। उर्वरक विभाग ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सिस्टम के सफल कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला, जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 में ₹1,77,129.50 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी आवंटित की गई है। यह सिस्टम पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) उपकरणों पर आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करता है, और जमाखोरी को रोकने के साथ-साथ किसानों तक पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए, प्रति किसान 50 बैग की मासिक सीमा और 300 बैग की मौसमी सीमा लागू करता है।

Science and Technology News

NIOT ने मौसम के पूर्वानुमान और ऑफशोर पवन ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए स्वदेशी फ्लोटिंग LiDAR बोय का परीक्षण किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वायत्त संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) ने मार्च 2026 में तमिलनाडु (TN) के कन्याकुमारी में मुत्तोम के तट पर, स्वदेशी रूप से विकसित फ्लोटिंग लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) बोय सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। फ्लोटिंग LiDAR बोय समुद्र पर आधारित एक उपकरण है, जो एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर लगी LiDAR तकनीक का उपयोग करके विभिन्न ऊंचाइयों पर ऑफशोर हवा की गति और दिशा को मापता है; यह गहरे समुद्र वाले उन क्षेत्रों में भी सटीक और लगातार डेटा प्रदान करता है, जहाँ पारंपरिक टावर लगाना संभव नहीं होता। यह तकनीक बेहतर वायुमंडलीय और समुद्र-संबंधी मॉडलिंग के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान और चक्रवात की भविष्यवाणी को बेहतर बनाती है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बेहतर मॉडलिंग, मूल्यांकन और अनुकूलन के द्वारा ऑफशोर पवन ऊर्जा को भी बढ़ावा देती है।

भारत सरकार ने ARCI हैदराबाद, तेलंगाना में रेयर अर्थ मैग्नेट पायलट प्लांट स्थापित किया। भारत सरकार (GoI) ने मार्च 2026 में हैदराबाद, तेलंगाना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (ARCI) में नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (Nd-Fe-B) रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए एक पायलट प्लांट स्थापित किया। यह नया स्थापित पायलट प्लांट एक एंड-टू-एंड प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिसमें स्ट्रिप-कास्ट अलॉय उत्पादन से लेकर तैयार सिंटर्ड मैग्नेट तक सब कुछ शामिल है, जिससे एक मजबूत और आत्मनिर्भर विनिर्माण प्रणाली विकसित करना संभव हो पाता है। ये उच्च-प्रदर्शन वाले मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), नवीकरणीय ऊर्जा (RE) प्रणालियों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक हैं, और इस पहल से आयात पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ वैश्विक रेयर अर्थ आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

ZSI के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र में कॉकरोच की नई प्रजाति 'Neoloboptera peninsularis' की खोज की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने मार्च 2026 में दक्कन प्रायद्वीप के कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से पुणे (महाराष्ट्र) के नाथाचीवाड़ी में, कॉकरोच की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम 'Neoloboptera peninsularis' रखा गया है। इस खोज को वैज्ञानिक पत्रिका 'Records of ZSI' में प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन में इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमी का उपयोग किया गया, जिसमें रूपात्मक विश्लेषण, जननांग अध्ययन, DNA बारकोडिंग और फाइलोजेनेटिक विश्लेषण को शामिल किया गया; यह भारत में DNA-आधारित कॉकरोच की पहली पहचान है। यह प्रजाति भारत में दर्ज 'Neoloboptera' वंश की तीसरी प्रजाति है, जिससे कॉकरोच की कुल प्रजातियों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है। यह संख्या वैश्विक कॉकरोच विविधता का लगभग 3.8% है, और यह इस बात की पुष्टि करती है कि यह प्रजाति भारत की ही मूल निवासी (स्थानिक) है।

IIT-खड़गपुर और PRL के वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम से भरपूर चंद्र बेसाल्ट के बनने का अध्ययन किया। IIT-खड़गपुर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL), अहमदाबाद के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर टाइटेनियम से भरपूर बेसाल्ट के बनने पर एक अध्ययन किया, जो मार्च 2026 में 'Geochimica et Cosmochimica Acta' में प्रकाशित हुआ। चंद्रमा की ज्वालामुखी चट्टानों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO_2) का स्तर असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा होता है; कुछ बेसाल्ट में तो 18% तक TiO_2 पाया जाता है, जबकि पृथ्वी की ज्वालामुखी चट्टानों में यह 2% से भी कम होता है। शोधकर्ताओं ने उच्च दबाव और उच्च तापमान वाले प्रयोगों के ज़रिए चंद्रमा के अंदरूनी हिस्सों की स्थितियों को कृत्रिम रूप से तैयार किया। इन प्रयोगों में चंद्रमा के भीतर 700 km तक की गहराई की स्थितियों को दोहराया गया। इन निष्कर्षों से भविष्य के चंद्र अभियानों—जिनमें भारत का 'चंद्रयान-4' अभियान (2028) भी शामिल है—की योजना बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Agnikul Cosmos ने दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D-प्रिंटेड बूस्टर इंजन 'Agnite' का सफल परीक्षण किया। Agnikul Cosmos Private Limited—जो अंतरिक्ष परिवहन के क्षेत्र में शुरू से आखिर तक सेवाएँ देने वाली एक कंपनी है—ने मार्च 2026 में तमिलनाडु (TN) के चेन्नई स्थित Agnikul Launchpad (ALP-01) पर अपने रॉकेट इंजन 'Agnite' का एक महत्वपूर्ण बूस्टर इंजन परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षण भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि (मील का पत्थर) साबित हुआ, क्योंकि Agnikul ने सफलतापूर्वक एक पूरे मीटर लंबे रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। 'Agnite' इंजन पूरी तरह से 3D-प्रिंटेड है, जिससे इसके निर्माण में लगने वाला समय 7 महीने से घटकर मात्र 7 दिन रह गया है। इसके परिणामस्वरूप, निर्माण लागत में भारी कमी आई है (जो घटकर दसवें हिस्से तक रह गई है) और उत्पादन क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस परीक्षण ने बड़े पैमाने पर 3D-प्रिंटिंग करने की क्षमता को प्रदर्शित किया है, जिससे Agnikul उन्नत एयरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित हो गया है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने मार्च 2026 में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) के तहत आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर एक बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। भारत में जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ते पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक खतरों से निपटने के लिए गठित इस समिति में उत्तराखंड के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, धनंजय मोहन को अध्यक्ष और केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति, ए. बीजू कुमार को दो साल के कार्यकाल के लिए सह-अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति आक्रामक विदेशी प्रजातियों की एक समेकित राष्ट्रीय सूची तैयार करेगी, उच्च जोखिम वाली प्रजातियों को प्राथमिकता देगी, और रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन तथा पारिस्थितिक बहाली के लिए विज्ञान-आधारित रणनीतियों की सिफारिश करेगी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्पादन पर्याप्तता योजना 2026–27 से 2035–36 जारी की। विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्च 2026 में नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित 'भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026' के दौरान 20वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण की मध्यावधि समीक्षा जारी की, जिसका शीर्षक "राष्ट्रीय उत्पादन पर्याप्तता योजना (2026–27 से 2035–36)" था। भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के लगभग 520 गीगावाट (31 जनवरी, 2026 तक) से बढ़कर 2035–36 तक 1,121 गीगावाट हो जाने का अनुमान है। 2035–36 तक ऊर्जा मिश्रण में सौर फोटोवोल्टिक क्षमता के सबसे आगे रहने की उम्मीद है, जिसकी क्षमता 509 गीगावाट (45 प्रतिशत हिस्सेदारी) होगी; इसके बाद कोयला-आधारित क्षमता 315 गीगावाट (28 प्रतिशत हिस्सेदारी) और पवन ऊर्जा 155 गीगावाट (14 प्रतिशत हिस्सेदारी) के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहेंगी।

एलन मस्क ने Terafab का अनावरण किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनने जा रही है। एलन मस्क ने मार्च 2026 में "Terafab" प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका मकसद रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के लिए इन-हाउस AI चिप्स बनाना है। यह प्रोजेक्ट ऑस्टिन, टेक्सास में स्थापित किया जाएगा और इसे Tesla और SpaceX मिलकर चलाएंगे, जिसमें xAI भी शामिल होगा। Terafab की शुरुआत एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन यूनिट से होगी, जो 2-नैनोमीटर चिप्स बनाएगी; इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $20–25 बिलियन है। उम्मीद है कि यह सुविधा सालाना 100–200 GW कंप्यूटिंग पावर को सपोर्ट करेगी और हर महीने 1 मिलियन चिप वेफर्स का उत्पादन करेगी। इसकी तुलना में, TSMC की योजना 2026 के अंत तक हर महीने 140,000 2-नैनोमीटर चिप वेफर्स बनाने की है।

अरुणाचल प्रदेश में BSI वैज्ञानिकों द्वारा जंगली कीवी की नई प्रजाति "Actinidia indica" की खोज। बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (BSI) के वैज्ञानिकों ने मार्च 2026 में अरुणाचल प्रदेश में जंगली कीवी की एक नई प्रजाति "Actinidia indica" की पहचान की। यह खोज अरुणाचल प्रदेश की ज़ीरो घाटी के पास 1,725 मीटर की ऊँचाई पर दर्ज की गई थी, जो भारत की वानस्पतिक विविधता को बढ़ाती है और पूर्वी हिमालय की पारिस्थितिक समृद्धि को उजागर करती है। यह प्रजाति समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय वनों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र में उगती है, जहाँ उच्च जैव विविधता और अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं; इससे Actinidia प्रजातियों की वैश्विक संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें से कुछ ही प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं।

रेगिस्तानी काई Syntrichia caninervis को भविष्य के मंगल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण माना गया। Syntrichia caninervis, एक लचीली रेगिस्तानी काई, को मार्च 2026 में भविष्य के मंगल उपनिवेशीकरण के लिए एक संभावित उम्मीदवार के रूप में पहचाना गया; इस अध्ययन को 'The Innovation' जर्नल में प्रकाशित किया गया था। यह काई अत्यधिक निर्जलीकरण, जमा देने वाले तापमान और तीव्र विकिरण में भी जीवित रह सकती है, जिससे यह कठोर परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक अनुकूलनीय बन जाती है। यह अपने कोशिकीय जल का 98% से अधिक हिस्सा खोकर भी एक सुप्त अवस्था में जा सकती है, और नमी के संपर्क में आने पर कुछ ही सेकंड में प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) फिर से शुरू कर सकती है। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, कम दबाव और UV विकिरण वाली मंगल जैसी कृत्रिम परिस्थितियों में परीक्षण किए जाने पर, यह काई कई दिनों तक जीवित रही और इसने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया; इसकी यह सहनशीलता इसके कुशल कोशिकीय मरम्मत तंत्र (cellular repair systems) के कारण है, जो उन क्षतियों को भी ठीक कर देता है जो अन्य जीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं।

BHASHINI पहल बहुभाषी डिजिटल शासन को बेहतर बनाती है। MeitY के तहत डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीज़न (DIBD) ने BHASHINI (राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन) को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में लागू किया, जो 36 भारतीय भाषाओं, 23 आवाज़ों और 35 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। AI-आधारित यह पहल रियल-टाइम अनुवाद और प्रासंगिक भाषा प्रोसेसिंग के लिए API और AI मॉडलों का उपयोग करती है, जिसमें स्पीच-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीकों वाले वॉइस-सक्षम इंटरफ़ेस शामिल हैं।

प्रोजेक्ट 'वायु बाण' ने स्वायत्त हेलीकॉप्टर-लॉन्च ड्रोन विकसित किया। भारतीय वायु सेना के एयरोस्पेस डिज़ाइन निदेशालय (DAD) ने मार्च 2026 में 'वायु बाण' प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके तहत एक छोटे स्वायत्त ड्रोन को डिज़ाइन करने के लिए 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' (RFP) जारी किया गया। इस ड्रोन को उड़ान के दौरान चलते हुए हेलीकॉप्टर से तैनात किया जाता है, और छोड़े जाने के बाद यह अपने पंख खोलता है और प्रोपल्शन (आगे बढ़ने की शक्ति) को सक्रिय करता है। यह प्रणाली 50+ किमी की स्टैंड-ऑफ एंगेजमेंट दूरी की अनुमति देती है, जिससे एयरक्रू MANPADS की मारक सीमा से सुरक्षित रहते हैं। इस क्षमता के साथ भारत, USA और चीन के बाद ऐसा तीसरा देश बन गया है।

IIT रोपड़ के ANNAM.AI ने 100 AI-आधारित मौसम स्टेशन लगाए। ANNAM.AI (IIT रोपड़ में सरकार द्वारा समर्थित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस) ने 30 मार्च, 2026 तक पूरे पंजाब में 100 AI-आधारित मौसम स्टेशन लगाने की पहल शुरू की। यह हाइपरलोकल रियल-टाइम मौसम डेटा सिस्टम किसानों को मुफ़्त में दिया जाता है। यह बुवाई, सिंचाई और फ़सल सुरक्षा से जुड़े फ़ैसलों को बेहतर बनाता है, जिससे खेती की उत्पादकता और जलवायु के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित एक डिजिटल सार्वजनिक संसाधन है, जिसका विस्तार हरियाणा, UP, केरल, ओडिशा, बिहार, J&K, HP और महाराष्ट्र तक करने की योजना है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल सुरक्षा के लिए Truecaller के साथ साझेदारी की। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने Truecaller के साथ मिलकर सुषमा स्वराज भवन में "TrueCyberSakhi: A Digital Safety Toolkit, Created for Her" पहल शुरू की। इस टूलकिट में इंटरैक्टिव मॉड्यूल, क्विज़ और सेल्फ़-असेसमेंट टूल शामिल हैं, जो स्पैम, फ़िशिंग, पहचान की चोरी, उत्पीड़न और वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही, यह NCW की 24×7 हेल्पलाइन पर मार्गदर्शन भी देता है। Truecaller की गवर्नमेंट डायरेक्टरी सर्विस (GDS) के ज़रिए सत्यापन होने से संस्थागत सहायता पर भरोसा और उसकी पहुँच बेहतर होती है।

NASA ने Artemis प्रोग्राम में एक बड़ा बदलाव करते हुए अपना ध्यान चंद्रमा की सतह पर बेस बनाने की ओर मोड़ दिया है। मार्च 2026 में, NASA ने 'Lunar Gateway' स्पेस स्टेशन बनाने की योजना को रद्द कर दिया और Artemis प्रोग्राम के तहत चंद्रमा की सतह पर $20 बिलियन की लागत से एक बेस बनाने की घोषणा की। इस काम के लिए NASA ने Apollo प्रोग्राम की तरह ही 'कदम-दर-कदम' आगे बढ़ने का तरीका अपनाया है। NASA के प्रमुख Jared Isaacman ने मंगल ग्रह के लिए एक न्यूक्लियर-पावर्ड मिशन की योजनाओं का भी खुलासा किया। इस मिशन के तहत, 2028 से पहले "Space Reactor 1 Freedom" नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उन्नत न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तकनीक और मंगल ग्रह पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर लगे होंगे। इस मिशन का लक्ष्य 2028 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है।

Important Days News

विश्व गौरैया दिवस 2026 – 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस (WSD) हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि गौरैया की आबादी में हो रही चिंताजनक कमी—खासकर घरेलू गौरैया (Passer domesticus) की—को उजागर किया जा सके, और उनके संरक्षण तथा शहरी जैव विविधता की सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। 20 मार्च, 2026 को WSD का 17वां आयोजन हुआ, जिसका 2026 का विषय था "पक्षियों के अनुकूल शहर और समुदाय बनाना।" WSD की शुरुआत मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित 'नेचर फॉरएवर सोसाइटी' (NFS) ने, 'इको-सिस एक्शन फाउंडेशन' (फ्रांस) के सहयोग से की थी; पहला WSD 20 मार्च, 2010 को मनाया गया था।

बच्चों और युवाओं के लिए विश्व रंगमंच दिवस 2026 – 20 मार्च। बच्चों और युवाओं के लिए विश्व रंगमंच दिवस हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है, ताकि युवाओं के सांस्कृतिक अधिकारों की वकालत की जा सके और जीवंत प्रदर्शन (live performance) की परिवर्तनकारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। 2026 का अभियान इस विषय पर केंद्रित है: "कला और संस्कृति के प्रति बच्चों के अधिकारों को मंच देना।" इस दिवस की स्थापना 2001 में 'बच्चों और युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संघ' (International Association of Theatre for Children and Young People) — जिसे फ्रेंच में Association Internationale du Théâtre de l'Enfance et la Jeunesse (ASSITEJ) कहा जाता है — द्वारा की गई थी; इसका पहला वैश्विक आयोजन 20 मार्च, 2001 को हुआ था।

नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 – 21 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) हर साल 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इसका मकसद नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव और अफ्रीकी मूल के लोगों व अन्य प्रभावित समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2026 में, नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (ICERD) की 61वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिवस पहली बार 21 मार्च, 1967 को मनाया गया था। इससे पहले, 26 अक्टूबर, 1966 को UN महासभा ने प्रस्ताव A/RES/2142 (XXI) को अपनाया था।

विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2026 – 21 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) हर साल 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस (WDSD) मनाता है। इसका उद्देश्य डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के अधिकारों, समावेश और भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें बढ़ावा देना है। 21 मार्च, 2026 को WDSD का 15वां आयोजन हुआ, जिसका विषय (Theme) था "अकेलेपन के खिलाफ एकजुट" (Together Against Loneliness)। यह वैश्विक जागरूकता अभियान 2006 में शुरू हुआ था। उस समय, डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन सिंगापुर ने डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल (DSi) की ओर से WDSD की वेबसाइट लॉन्च की और उसे होस्ट किया (2006–2010)। इसके बाद, 19 दिसंबर, 2011 को UN ने प्रस्ताव A/RES/66/149 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 21 मार्च को WDSD घोषित कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय नवरोज़ दिवस 2026 – 21 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) का अंतर्राष्ट्रीय नवरोज़ दिवस हर साल 21 मार्च को दुनिया भर में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शांति, एकजुटता और अच्छे पड़ोस के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 23 फरवरी, 2010 को, UNGA ने प्रस्ताव A/RES/64/253 को अपनाया, जिसमें आधिकारिक तौर पर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज़ दिवस घोषित किया गया; पहला अंतर्राष्ट्रीय नवरोज़ दिवस 21 मार्च, 2010 को मनाया गया था। 2009 में, नवरोज़ को UNESCO की 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची' में शामिल किया गया था।

विश्व कविता दिवस 2026 – 21 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) हर साल 21 मार्च को दुनिया भर में विश्व कविता दिवस मनाता है, जिसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और कविता के माध्यम से लुप्तप्राय भाषाओं का समर्थन करना है। 21 मार्च, 2026 को 27वां विश्व कविता दिवस मनाया गया, जिसका 2026 का विषय था "शांति और समावेशन के लिए कविता एक सेतु के रूप में।" 1999 में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अपने 30वें आम सम्मेलन के दौरान 21 मार्च (उत्तरी गोलार्ध में वसंत का पहला दिन) को विश्व कविता दिवस घोषित किया; पहला विश्व कविता दिवस 21 मार्च, 2000 को मनाया गया था।

विश्व ग्लेशियर दिवस 2026 – 21 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) का विश्व ग्लेशियर दिवस हर साल 21 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मकसद ग्लेशियरों को बचाने की तत्काल ज़रूरत को उजागर करना है, और पारिस्थितिकी तंत्र, ताज़े पानी की आपूर्ति और जलवायु स्थिरता में उनकी अहम भूमिका पर ज़ोर देना है। 21 मार्च, 2026 को दूसरा विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा प्रस्ताव A/RES/77/158 (2022) के ज़रिए की गई घोषणा के बाद मनाया गया; पहला विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च, 2025 को मनाया गया था। UNGA ने 2025 को 'ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया, जिसे UNESCO और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का समर्थन मिला।

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 – 21 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस (IDF) हर साल 21 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मकसद सभी तरह के वनों का उत्सव मनाना, और उनके महत्व तथा उन्हें बचाने की ज़रूरत के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। 21 मार्च, 2026 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, जिसका 2026 का विषय था "वन और अर्थव्यवस्थाएँ"। UNGA ने 21 दिसंबर, 2012 को प्रस्ताव A/RES/67/200 के ज़रिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, 2013 को मनाया गया था, जिसका आयोजन UN के 'वन मंच' (UNFF) और 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) ने मिलकर किया था।

विश्व कठपुतली दिवस 2026 – 21 मार्च। विश्व कठपुतली दिवस (WPD) हर साल 21 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मकसद कठपुतली कला को एक वैश्विक कला रूप और शिक्षा के साधन के तौर पर मनाना और दुनिया भर के कठपुतली कलाकारों को सम्मानित करना है। WPD की शुरुआत 2003 में UNIMA (यूनियन इंटरनेशनेल डे ला मैरियोनेट) ने की थी, ताकि दुनिया भर के कठपुतली कलाकारों को एक मंच पर लाया जा सके। पहला WPD 21 मार्च, 2003 को मनाया गया था। WPD के सालाना आयोजन की अगुवाई UNIMA करता है। यह दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय थिएटर संगठन है और UNESCO से जुड़ा एक NGO है।

विश्व जल दिवस 2026 – 22 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) का विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मकसद ताज़े पानी के महत्व पर ज़ोर देना और दुनिया भर में पानी के संकट के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2026 का विषय है "जल और लिंग", जिसका उप-विषय है "जहाँ पानी बहता है, वहाँ समानता पनपती है।" यह दिवस पहली बार 22 मार्च, 1993 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के बाद हुई थी। विश्व जल दिवस का सालाना आयोजन 'संयुक्त राष्ट्र जल' (UN-Water) द्वारा किया जाता है। इसकी अगुवाई इसके एक या एक से ज़्यादा सदस्य और सहयोगी करते हैं, जिनके पास इस विषय से जुड़े ज़रूरी अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं।

विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 – 23 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) का विश्व मौसम विज्ञान दिवस (WMD) हर साल 23 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मकसद मौसम और जलवायु को समझने की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाना और 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की औपचारिक स्थापना की याद दिलाना है। 2026 का विषय है "आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा।" WMD की घोषणा WMO ने अपने 12वें कार्यकारी समिति सत्र (EC-XII) के दौरान की थी। यह सत्र 27 जून से 15 जुलाई, 1960 तक चला था, जिसमें प्रस्ताव 6 (EC-XII) को अपनाते हुए 23 मार्च को WMD घोषित किया गया था। इसे पहली बार 23 मार्च, 1961 को मनाया गया था।

शहीद दिवस 2026 – 23 मार्च। शहीद दिवस या शहीदों का दिन हर साल 23 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्हें अंग्रेजों ने फाँसी दे दी थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या भी शामिल थी। 23 मार्च, 1931 को ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल (जो अब पाकिस्तान में है) में फाँसी दे दी थी। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) हर साल पूरे भारत में शहीद दिवस का आयोजन करता है।

विश्व क्षय रोग दिवस 2026 – 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस (WTD) हर साल 24 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मकसद क्षय रोग (TB) के बारे में जागरूकता फैलाना है—यह एक ऐसा संक्रामक रोग है जिसे रोका और ठीक किया जा सकता है—और इसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिशों को तेज़ करना है। 2026 की थीम है: "हाँ! हम TB खत्म कर सकते हैं! देशों की अगुवाई में, लोगों की ताकत से।" 1982 में, कोच की खोज की सौवीं वर्षगांठ पर, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज (IUATLD) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 24 मार्च को विश्व TB दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव रखा था। पहला आधिकारिक विश्व TB दिवस 24 मार्च, 1983 को मनाया गया था।

मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से जुड़े सच के अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस – 24 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) का 'मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से जुड़े सच के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' हर साल 24 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मकसद मानवाधिकारों के गंभीर हनन के पीड़ितों को सम्मान देना और न्याय को बढ़ावा देना है। यह दिन अल सल्वाडोर के मॉन्सिग्नोर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमेरो की याद में भी मनाया जाता है, जिनकी 24 मार्च, 1980 को उत्पीड़न और हिंसा का विरोध करने के कारण हत्या कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 21 दिसंबर, 2010 को प्रस्ताव A/RES/65/196 पारित किया, जिसके तहत 24 मार्च को आधिकारिक तौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह दिवस पहली बार 24 मार्च, 2011 को मनाया गया था।

गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 – 25 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) का 'गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' हर साल 25 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह उन लाखों लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के दौरान कष्ट सहे, जो इतिहास में मानवाधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन था। 2026 का विषय है: "न्याय की कार्रवाई: इतिहास का सामना, गरिमा को बढ़ावा, भविष्य को सशक्त बनाना।" संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 17 दिसंबर, 2007 को प्रस्ताव A/RES/62/122 पारित किया, जिसमें 25 मार्च को इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया; यह दिवस पहली बार 25 मार्च, 2008 को मनाया गया था।

हिरासत में लिए गए और लापता कर्मचारियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 – 25 मार्च। संयुक्त राष्ट्र (UN) का 'हिरासत में लिए गए और लापता कर्मचारियों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। यह उन कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्हें शांति और मानवीय मिशनों के दौरान हिरासत, अपहरण या हिंसा का सामना करना पड़ता है। यह दिवस 1985 में एलेक कोलेट के अपहरण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। एलेक कोलेट 'निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी' (UNRWA) के पत्रकार थे, जिनका लेबनान में 'अबू निदाल समूह' द्वारा अपहरण कर लिया गया था।

विश्व रंगमंच दिवस 2026 – 27 मार्च को मनाया गया। 27 मार्च, 2026 को विश्व भर में विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। यह इस वार्षिक उत्सव का 64वां आयोजन था, जो रंगमंच के सांस्कृतिक महत्व और वैश्विक एकता को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को मान्यता देता है। वर्ष 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान (ITI) द्वारा शुरू किया गया यह दिवस—जिसकी स्थापना 1948 में UNESCO द्वारा की गई थी—पहली बार 27 मार्च, 1962 को मनाया गया था। यह तिथि पेरिस में 'थिएटर ऑफ नेशंस' (Theatre of Nations) के सत्र के उद्घाटन का प्रतीक थी। वर्ष 2026 का उत्सव 25 से 27 मार्च तक लक्ज़मबर्ग शहर, लक्ज़मबर्ग में आयोजित किया गया।

अर्थ आवर 2026, 28 मार्च को मनाया गया। अर्थ आवर 2026 को 28 मार्च, 2026 को विश्व स्तर पर मनाया गया, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम का 20वां वर्ष था। इस अभियान ने ग्रह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में, रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच गैर-ज़रूरी बिजली की बत्तियाँ बंद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। अर्थ आवर को पहली बार WWF द्वारा 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया (31 मार्च, 2007) में पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए "लाइट्स ऑफ" पहल के रूप में शुरू किया गया था।

Obituaries News

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद 'दत्ता मेघे' का निधन। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद (MP) 'दत्ता मेघे' का मार्च 2026 में महाराष्ट्र में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 11 नवंबर, 1936 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पवनार गांव में हुआ था; उनका राजनीतिक करियर पांच दशकों से अधिक समय तक कई विधायी निकायों में फैला रहा। वह पहली बार 1978 में महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) के लिए चुने गए थे और 1991 तक लगातार तीन कार्यकाल तक सेवा की; उन्होंने नागपुर, रामटेक और वर्धा से चार बार लोकसभा सांसद के रूप में कार्य किया, और 2002 से 2008 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में भी सेवा दी।

फ्रांस के पूर्व PM लियोनेल जोस्पिन, 35-घंटे के कार्य-सप्ताह के सूत्रधार, का निधन। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री (PM) लियोनेल रॉबर्ट जोस्पिन का मार्च 2026 में फ्रांस के पेरिस में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 12 जुलाई, 1937 को फ्रांस के पेरिस के पास, मेउडन में हुआ था, और उन्होंने राष्ट्रपति जैक्स शिराक के कार्यकाल में 1997 से 2002 तक फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 'पैरिटी लॉ' (समानता कानून) लागू किया और LGBTQ+ तथा विषमलिंगी (heterosexual) दोनों तरह के जोड़ों के लिए 'सिविल यूनियन' (CU) की शुरुआत की; साथ ही उन्होंने कार्य-सप्ताह को 39 घंटे से घटाकर 35 घंटे कर दिया, जो फ्रांस में एक ऐतिहासिक श्रम सुधार था।

बिरुते गाल्डिकास, जानी-मानी ओरंगुटान विशेषज्ञ, का 79 वर्ष की आयु में निधन। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ओरंगुटान शोधकर्ता बिरुते गाल्डिकास का मार्च 2026 में, 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बोर्नियो में वन्यजीव अनुसंधान के क्षेत्र में दशकों तक काम किया और अपने अग्रणी क्षेत्रीय अध्ययनों तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से लुप्तप्राय ओरंगुटान प्रजातियों को समझने और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ई. ए. राजेंद्रन, अनुभवी मलयालम अभिनेता, का 71 वर्ष की आयु में निधन। अनुभवी मलयालम अभिनेता और रंगमंच कलाकार ई. ए. राजेंद्रन का मार्च 2026 में, लंबी बीमारी के बाद 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दशकों तक फैले अपने विशिष्ट करियर के माध्यम से उन्होंने मलयालम फिल्म उद्योग और रंगमंच कला समुदाय पर गहरा प्रभाव छोड़ा।

Miscellaneous News

लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। लोकसभा ने मार्च 2026 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। यह विधेयक "ट्रांसजेंडर" शब्द को फिर से परिभाषित करता है, जिसमें यौन रुझान और स्वयं द्वारा महसूस की गई लैंगिक पहचान को इसके दायरे से बाहर रखा गया है; इसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में स्पष्टता लाना है। संशोधित परिभाषा पारंपरिक और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ट्रांसजेंडर समुदायों पर केंद्रित है, जिसमें हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जोगता और इंटरसेक्स विभिन्नताओं वाले व्यक्ति शामिल हैं। यह संशोधन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग-अलग स्तर के दंड का प्रावधान करता है, जिसमें अधिकतम सज़ा को 2 साल (2019 के अधिनियम के तहत) से बढ़ाकर 14 साल की कैद कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ईसाई धर्म अपनाने के बाद SC का दर्जा समाप्त। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जो हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म को मानते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईसाई धर्म अपनाने पर SC का दर्जा तत्काल समाप्त हो जाता है, चाहे व्यक्ति की जन्म-पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। इस फैसले ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले के एक निर्णय को बरकरार रखा, जिससे संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के तहत जाति-आधारित आरक्षण और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे को और मजबूती मिली है।

पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी ने तटीय मछुआरा समुदायों की मदद के लिए 'ब्लू वॉयस' मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी ने मार्च 2026 में तटीय मछुआरा समुदायों के बीच सुरक्षा और आपदा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए 'ब्लू वॉयस' नाम का एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। इस पहल का मकसद अहम जानकारी की कमी को दूर करना है। इसके तहत, मौसम से जुड़ी ताज़ा और जगह-विशेष की जानकारी आसान और सुलभ तरीके से दी जाएगी। इसका इंटरफ़ेस इस्तेमाल करने में आसान है, जो उन लोगों के लिए भी मुफ़ीद है जिनकी डिजिटल साक्षरता सीमित है। यह ऐप तटीय इलाकों के हिसाब से मौसम का सटीक और ताज़ा डेटा देता है। इससे मछुआरों को तूफ़ान, हवा के रुख़ और समुद्र की स्थिति के बारे में समय पर अलर्ट मिलते हैं, जिससे वे मौसम में अचानक होने वाले बदलावों का पहले से अंदाज़ा लगा पाते हैं।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने स्मार्ट हेल्थकेयर में 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' लॉन्च किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश—जो भारत की पहली निजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस बहु-विषयक यूनिवर्सिटी है—ने मार्च 2026 में स्मार्ट हेल्थकेयर में एक 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' लॉन्च किया। इसका मकसद राज्य के AI-आधारित हेल्थकेयर और शासन के विज़न को मज़बूत करना है। इस 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' की अगुवाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफ़ेसर और प्रो-वाइस चांसलर, थिपेंद्र पी. सिंह कर रहे हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) सिस्टम से चलता है, जिसमें 168 गीगाबाइट की मेमोरी है। यह NVIDIA Blackwell आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो उच्च-स्तरीय शोध और AI मॉडल के विकास को संभव बनाता है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का पहला LPG ATM लॉन्च किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2026 में गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया। यह पहल 'भारतगैस इंस्टा LPG' पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी इलाकों में 24 घंटे LPG सिलेंडर की ऑटोमेटेड (स्वचालित) डिलीवरी सुनिश्चित करना है। यह LPG ATM सिलेंडर की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करता है, खासकर सप्लाई में रुकावट या आपातकालीन स्थितियों के दौरान। इसकी मुख्य विशेषताओं में मोबाइल OTP (वन-टाइम पासवर्ड) आधारित ग्राहक सत्यापन, QR कोड या बारकोड स्कैनिंग, और UPI व डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान शामिल हैं।

ROBs के लिए मंज़ूरी की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और तेज़ करने हेतु PRISM-SG पोर्टल लॉन्च किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में PRISM-SG (रेल-सड़क निरीक्षण और चरण प्रबंधन – स्टील गर्डर्स के लिए पोर्टल) पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास में दक्षता, पारदर्शिता और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। PRISM-SG पोर्टल को 'रोड ओवर ब्रिज' (ROBs) के निर्माण से जुड़ी मंज़ूरी और निरीक्षण की मुख्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से दस्तावेज़ों को ऑनलाइन जमा करना, उनकी जांच-पड़ताल, सवालों को उठाना और उनका समाधान करना, मंज़ूरी प्राप्त करना और निरीक्षण का समय निर्धारित करना—ये सभी प्रक्रियाएं शुरू से अंत तक ऑनलाइन पूरी की जा सकेंगी। उम्मीद है कि इस पहल से मंज़ूरी और निरीक्षण में लगने वाला समय लगभग 12 महीने से घटकर 3-4 महीने रह जाएगा।

राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट BSE पर लिस्ट हुआ, 14 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT), मार्च 2026 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट हुआ। RIIT के पहले पब्लिक इश्यू को ज़बरदस्त सफलता मिली; इसे लगभग 14 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और हाईवे एसेट्स में निवेशकों के मज़बूत भरोसे को दिखाता है। RIIT का मकसद नेशनल हाईवे एसेट्स से कमाई करना है, जिसका लक्ष्य अगले 3 सालों में 1,500 km हाईवे से कमाई करना है।

GHADC ने मेघालय में काउंसिल चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट अनिवार्य किया। मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 24 मार्च, 2026 को एक संशोधन पास किया, जिसके तहत काउंसिल के चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संशोधन का मकसद काउंसिल के आदिवासी स्वरूप को मज़बूत करना है, जिसके लिए चुनाव लड़ने की पात्रता को सिर्फ़ मेघालय की मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तक ही सीमित कर दिया गया है। इससे पहले 17 फरवरी, 2026 को जारी एक नोटिफिकेशन में भी इसी तरह का नियम लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेघालय हाई कोर्ट ने प्रक्रियागत खामियों के चलते उसे रद्द कर दिया था; अब यह संशोधन उचित विधायी प्रक्रिया का पालन करते हुए लाया गया है।

रक्षा मंत्री ने BRO पर रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन (BRO) पर रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा परिचालन तत्परता के लिए रणनीतिक पहलों पर चर्चा की गई। BRO ने रक्षा बलों की गतिशीलता को बढ़ाया है और स्थानीय निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है; इस संगठन को भारत-म्यांमार सीमा (जो लगभग 1,600 किमी लंबी है) के साथ बुनियादी ढांचा विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। 1960 में अपनी स्थापना के बाद से, BRO ने 64,000 किमी से अधिक सड़कें, 1,179 पुल, 22 हवाई क्षेत्र और 7 सुरंगें बनाई हैं।

ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ अमेरिकी मुद्रा के डिज़ाइन में बदलाव की घोषणा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने मार्च 2026 में घोषणा की कि जून 2026 से अमेरिकी मुद्रा नोटों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। यह अमेरिकी मुद्रा के डिज़ाइन में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जो राष्ट्रपति पद की परंपराओं में हुए अद्यतनों को दर्शाता है।

TV रेटिंग पॉलिसी (TRP) 2026 जारी - ज़्यादा पारदर्शिता के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 27 मार्च, 2026 को TV रेटिंग पॉलिसी 2026 जारी की। इस पॉलिसी के तहत TV रेटिंग एजेंसियों के लिए ज़रूरी न्यूनतम नेट वर्थ को ₹20 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही, 50% स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors) का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, मीटर वाले घरों की संख्या को बढ़ाकर 80,000 (18 महीनों में) और आखिरकार 1,20,000 घरों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी में तिमाही आंतरिक और वार्षिक बाहरी ऑडिट की व्यवस्था की गई है। शिकायतों के 10 दिनों के भीतर समाधान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग तरह के दंड (अस्थायी निलंबन से लेकर पंजीकरण रद्द करने तक) का प्रावधान है। ये सभी कदम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और निजता के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।

वित्तीय सेवा विभाग ने लंबे समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा की। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने 2024 से अब तक 18 वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं। इन कॉन्फ्रेंस में RBI, IRDAI, बैंकों, बीमा कंपनियों और CPGRAMS के 20 रैंडमली चुने गए शिकायतकर्ताओं के साथ कुल 360 शिकायतों की समीक्षा की गई। कुछ प्रमुख समाधानों में शामिल हैं: ₹2,00,000 का PMSBY दावा (PNB, जून 2025), ₹9,65,000 का LIC सुपरएन्यूएशन (जून 2025), ₹33,058 का पेंशन बकाया (BoM, जुलाई 2025), ₹18,53,121 का HDFC Ergo मेडिकल दावा (अक्टूबर 2025), ₹13,30,000 का Axis Max मृत्यु दावा (दिसंबर 2025), ₹10,00,000 का Canara HSBC मिस-सेलिंग मामला (दिसंबर 2025), और 2003 से लंबित ₹14,75,299 की पारिवारिक पेंशन (फरवरी 2026)। ये सभी उदाहरण एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को दर्शाते हैं, जो शासन में पारदर्शिता को मज़बूत करता है।

Static Takeaways

श्रेणी	इकाई	मुख्य विवरण
मंत्रालय	वित्त मंत्रालय	मंत्री: निर्मला सीतारमण
संगठन	विश्व व्यापार संगठन (WTO)	स्थापना: 1995; मुख्यालय: जेनेवा; महानिदेशक: न्गोज़ी ओकोंजो-इवेला; सदस्य: 166
संगठन	सेबी (SEBI)	स्थापना: 1988; मुख्यालय: मुंबई; अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे
संगठन	इरडाई (IRDAI)	स्थापना: 1999; मुख्यालय: हैदराबाद; अध्यक्ष: अजय सेठ
संगठन	नाबार्ड (NABARD)	स्थापना: 1982; मुख्यालय: मुंबई; अध्यक्ष: शाजी के. वी
संगठन	नीति आयोग	स्थापना: 2015; उपाध्यक्ष: सुमन बेरी; CEO: निधि छिब्बर
संगठन	आईसीएआई (ICAI)	स्थापना: 1949; मुख्यालय: नई दिल्ली; अध्यक्ष: चरणजीत सिंह नंदा
संगठन	सीसीआई (CCI)	स्थापना: 2003; मुख्यालय: नई दिल्ली; अध्यक्ष: रवनीत कौर
संगठन	पीएफआरडीए (PFRDA)	स्थापना: 2003; मुख्यालय: नई दिल्ली; अध्यक्ष: शिवसुब्रमण्यम रमन्न
संगठन	यूनेस्को (UNESCO)	स्थापना: 1945; मुख्यालय: पेरिस; महानिदेशक: खालिद एल-एनानी

श्रेणी	इकाई	मुख्य विवरण
संगठन	अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति	स्थापना: 1894; मुख्यालय: लॉज़ेन; अध्यक्ष: कर्स्टी कोवेंट्री
बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	स्थापना: 1908; मुख्यालय: वडोदरा; CEO: देबदत्ता चंद
बैंक	साउथ इंडियन बैंक	स्थापना: 1929; मुख्यालय: त्रिशूर; CEO: पी. आर. शेषाद्रि
बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	स्थापना: 2025; मुख्यालय: बल्लारी; अध्यक्ष: श्रीकांत एम. भंडिवाड
राज्य	हरियाणा	मुख्यमंत्री: नायब सिंह सैनी; राज्यपाल: अशिम कुमार घोष; राजधानी: चंडीगढ़
राज्य	उत्तर प्रदेश	मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल; राजधानी: लखनऊ
राज्य	तेलंगाना	मुख्यमंत्री: रेवंत रेड्डी; राज्यपाल: शिव प्रताप शुक्ल; राजधानी: हैदराबाद
राज्य	पंजाब	मुख्यमंत्री: भगवंत मान; राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया; राजधानी: चंडीगढ़
केंद्र शासित प्रदेश	दिल्ली	मुख्यमंत्री: रेखा गुप्ता; उपराज्यपाल: वी. के. सक्सेना; राजधानी: नई दिल्ली
देश	इंडोनेशिया	राजधानी: जकार्ता; राष्ट्रपति: प्रबोवो सुबियांतो; मुद्रा: रुपिया
देश	भूटान	राजधानी: थिम्फू; राजा: जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक
देश	इटली	राजधानी: रोम; राष्ट्रपति: सर्जियो मटरेल्ला; मुद्रा: यूरो
मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	मंत्री: शिवराज सिंह चौहान
मंत्रालय	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	मंत्री: नितिन गडकरी
मंत्रालय	रक्षा मंत्रालय	मंत्री: राजनाथ सिंह
मंत्रालय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	मंत्री: वीरेंद्र कुमार खटीक